

संक्षिप्त खबरें

झारखंड के छह जिलों में 14 अगस्त को बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

रांची। झारखंड के छह जिलों में 14 अगस्त को बहुत भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गुमला और लोहरदगा शामिल हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी। विभाग के अनुसार, 16 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। इसे देखते हुए राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। हालांकि, एक जून से 12 अगस्त तक झारखंड में कुल 492.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 627.6 मिलीमीटर है। इस लिहाज से राज्य में अब तक सामान्य से 21 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है।

राज्यसभा से केरल नाम परिवर्तन विधेयक पारित, केरल का नाम होगा केरलम

नई दिल्ली। संसद ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित करते हुए केरल का नाम बदलकर ह्यकेरलमह्द करने को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया, जबकि लोकसभा ने इसे मंगलवार को ही मंजूरी दे दी थी। केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में दर्ज राज्य के नाम को संशोधित कर केरल से केरलम करना है। केरल विधानसभा ने वर्ष 2024 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार से राज्य का नाम बदलने के लिए कानून लाने की सिफारिश की थी। इसके बाद केन्द्र सरकार ने विधेयक को अगे बढ़ाया। विधेयक के पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद आधिकारिक रूप से राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाएगा। राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा के बाद इस पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह बदलाव राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के उद्देश्य से किया गया है।

जनगणना-2027 की तैयारियां तेज, 31 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में मकान सूचीकरण का काम पूरा

नई दिल्ली। देश में जनगणना-2027 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना का काम 31 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है। बाकी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में यह काम सितंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। भारत के राजपत्र में 03 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के

बिहान भारत

झारखंड के 29 पुलिस अधिकारियों-कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा पुलिस पदक

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड के तीन भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों समेत 29 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनकी विशिष्ट, वीरतापूर्ण और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। गृह विभाग ने पदक पाने वाले अधिकारियों और कर्मियों की सूची जारी कर दी है।

एएसआई के विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, पांच पुलिसकर्मीयों को वीरता पदक और तीन आईपीएस अधिकारियों समेत 23 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। इस बार सम्मान पाने वालों में पांच महिला पुलिसकर्मी भी शामिल



हैं। विशिष्ट सेवा के लिए जैप-1 के एएसआई कैलाश प्रसाद श्रेष्ठ को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं, वीरता पदक पाने वालों में लातेहार के अवर निरीक्षक विनय कुमार, आईआरबी-4 लातेहार के सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार राय, लातेहार जिला बल के आरक्षी वेद प्रकाश महतो और रामचंद्र कुमार महतो तथा आईआरबी-1 जामताड़ा के आरक्षी कृष्णा मुर्मू शामिल हैं। सराहनीय सेवा के लिए पदक पाने

वालों में महानिरीक्षक रेल डॉ. माइकल राज एस. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईपीएस अधिकारी अन्नेपु विजयालक्ष्मी और कोल्हान के उपमहानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा शामिल हैं। इनके अलावा स्पेशल बांच के उपाधीक्षक नीरज कुमार, वायरलेस के इंस्पेक्टर अरुण कुमार, एसटीएफ के इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय, आईटीएस रांची के इंस्पेक्टर अंसित कुमार मोदी, एसटीएफ के एएसआई अरविंद कुमार पालित, वशिष्ठ कुंवर, संजीव कुमार झा और विजय कुमार

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन 19वें दिन जारी

बिभा संवाददाता

रांची। जेपीएससी-जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन बुधवार को लगातार 19वें दिन भी जारी रहा। वहीं, आमरण अनशन का नौवां दिन रहा। आंदोलनकारी छात्र परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। आंदोलनकारी छात्र विनय मेहता ने कहा कि छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। देर रात धरना स्थल पर पुलिस प्रशासन की सक्रियता को लेकर उन्होंने आशंका जताई कि कहीं आंदोलन को दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। उन्होंने



सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। इसी बीच, आंदोलनकारी उम्मा हबीब की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले छात्र-अभ्यर्थी राहुल कुमार और देवेंद्रनाथ महतो को भी सदर अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया था। आंदोलनकारियों ने कहा कि अनशनकारियों का इलाज जारी रहने के बावजूद देर रात धरना स्थल पर प्रशासन की मौजूदगी कई

सवाल खड़े करती है। छात्र आंदोलनकारी कुणाल प्रताप सिंह समेत अन्य ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों में उठे सवालों का स्पष्ट और संतोषजनक समाधान जरूरी है। उनका आरोप है कि सरकार मामले की गंभीरता से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ा है। पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि

को भी सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा। रांची जिला के एएसआई दीपक पुंज, सीआईडी के एएसआई महेंद्र महतो, एसटीएफ के हवलदार इकबाल, हवलदार बिन्दरारा मुण्डरी और हवलदार विजय थापा भी सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित होंगे। इस बार पदक पाने वालों में पांच महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। जैप-10 होटवार की महिला आरक्षी मानी खलखो और प्रभा देवी तथा महिला हवलदार रंजिता कुजूर को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जैप-10 की महिला आरक्षी पुष्पा ओडेया को भी सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किया जाएगा। गढ़वा के आरक्षी विदेशी मांझी, चतरा के आरक्षी अजय कुमार दूबे और गुमला के आरक्षी दीपक कुमार सिंह को भी

सराहनीय सेवा पदक मिलेगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया है कि पदक प्राप्त करने वाले अधिकारी और कर्मी 13 अगस्त 2026 की अपराह्न तक वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के समक्ष रिपोर्ट करें। पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी पदक प्राप्तकर्ता का इस बीच स्थानांतरण या पदस्थापन हो गया है तो संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक अथवा नियंत्रक पदाधिकारी इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया जाने वाला यह सम्मान पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशिष्ट, वीरतापूर्ण एवं सराहनीय सेवाओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन का इस्तीफा

नई दिल्ली। टाटा समूह से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है और वे दोबारा से अपॉइन्मेंट की मांग नहीं करेंगे। एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 में पूरा होगा। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कंपनी की 18 अगस्त को होने वाली सालाना आम बैठक से पहले पद छोड़ने का एलान किया है, और बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। दरअसल, डायरेक्टर के तौर पर उनके दोबारा चुने जाने को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही थी और टाटा ग्रुप के अंदर तनाव बना हुआ था। एन चंद्रशेखरन ने कहा, मैंने टाटा ग्रुप में अपने प्रोफेशनल जीवन के 40 साल पूरे कर लिए हैं। इस प्रतिष्ठित संस्थान में योगदान देने का मौका मिलना मेरे लिए बेहद संतोषजनक रहा है और मैं इसके लिए आभारी हूँ। पिछले एक दशक से टाटा संस का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी की बात रही है।

सरकार संसद में नीट परीक्षा को लेकर

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि सरकार संसद में नीट परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से चर्चा कर इस विषय पर चर्चापत्र समय आवंटित करने का अनुरोध किया है। अमित शाह ने पत्र में कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन

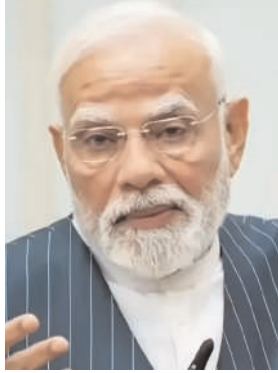


के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमत दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आग्रह पर पहले ही संसद के मौजूदा सत्र में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की

भारत में दुनिया के 60 प्रतिशत से अधिक जंगली एशियाई हाथी, 33 अभयारण्य संरक्षण प्रयासों को दे रहे मजबूती : पीएम मोदी

एजेंसी

नई दिल्ली। विश्व हाथी दिवस पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाथी को भारत की पारिस्थितिकी विरासत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए देश के मजबूत संरक्षण प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया के 60 प्रतिशत से अधिक जंगली एशियाई हाथी पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 33 हाथी अभयारण्य हैं, जो हाथियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके दीर्घकालिक संरक्षण के प्रयासों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मोदी ने हाथी संरक्षण के प्रयासों में योगदान देने वाले वनकर्मियों, वैज्ञानिकों, पशु चिकित्सकों, महावतों और स्थानीय समुदायों के प्रति गर्व और आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ह्याएक्ससह पर एक पोस्ट में कहा कि विश्व हाथी दिवस पर हम उस विशालकाय और गौरवशाली हाथी का उत्सव मनाते हैं, जो भारत की पारिस्थितिकी विरासत का



अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि भारत दुनिया के 60 प्रतिशत से अधिक जंगली एशियाई हाथियों का घर है। उन्होंने कहा कि देश के 33 हाथी अभयारण्य हाथियों के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं और उनके दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री ने संरक्षण से जुड़े सभी वनकर्मियों, वैज्ञानिकों, पशु चिकित्सकों, महावतों और स्थानीय समुदायों की भूमिका की भी सराहना की।

छात्रों की मांगों को सरकार ने एक सप्ताह में माना तो करेंगे अनशन : रघुवर दास

बिभा संवाददाता

रांची। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र-अभ्यर्थियों से मिलने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों और अब तक चले आंदोलन की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए छात्रों की मांगों पर एक सप्ताह में सकारात्मक निर्णय लेने का समय दिया।



मौके पर रघुवर दास ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर सरकार छात्रों की जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो वह स्वयं आंदोलन में उतरेंगे। उन्होंने घोषणा की कि एक सप्ताह बाद बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थल पर अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेकर सरकार

को उचित समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करे। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को दबाने के बजाय उनकी मांगों पर बातचीत कर समाधान निकालने की जरूरत है। रघुवर दास ने आंदोलनकारी छात्रों से कहा कि उनके भविष्य और अधिकार से जुड़े इस संघर्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके एक सप्ताह के अल्टीमेटम और इसके बाद अनशन की घोषणा से छात्र आंदोलन को लेकर राजनीतिक सरगमी बढ़ गई है।

छात्र आंदोलन पर चर्चा को तैयार : शाह

रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए फिर तैयार है। गृहमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि विपक्ष से चर्चा कर आपसी सहमति से आज से जितना समय और जितने घंटे उचित समझें, उतना समय इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के दौरान वह सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर

चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। शाह ने कहा कि लोकतंत्र में चर्चा और संवाद से ही समाधान निकलता है। उन्होंने कहा कि उन्हें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अटूट विश्वास है और उनका मानना है कि सदन चर्चा और संवाद के लिए ही है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से विपक्ष के नेताओं से चर्चा कर इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में अच्छा वातावरण बनाने का आग्रह किया ताकि पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य इस मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकें।

राज्यसभा से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित

नई दिल्ली। राज्यसभा ने बुधवार को करीब एक घंटे तक चली चर्चा के बाद राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले यह विधेयक मंगलवार को लोकसभा से भी पारित हो चुका है। इस बीच कांग्रेस ने सदन से गृहमंत्री के सदन में जवाब की मांग को लेकर बहिर्गमन किया। सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) अधिनियम, 1962 में संशोधन करता है, जिससे सहकारी समितियों को सीधा वित्त पोषण और ऋण मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की



वित्तीय क्षमता और अधिकारों का विस्तार करना है ताकि वह सहकारी क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं और परिवोजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से वित्तीय सहायता दे सके। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोले ने कहा कि देश में 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं, जिनसे करीब 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद पिछले पांच वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 3,000 करोड़ रुपये की

लागत से देश की 80,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक का कानून बनने से अब पात्र सहकारी समितियों और सहकारिता विकास से जुड़ी संस्थाओं को सीधे ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगा। निगम के सहायता दायरे में कृषि और पशुधन के अलावा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वस्तुएं भी शामिल की गई हैं। विभिन्न सहकारी संस्थाओं और विकास से जुड़ी इकाइयों की शेयर पूंजी में भी निवेश कर सकेगा। औद्योगिक वस्तुओं और संबंधित सेवाओं पर लागू कुछ पुराने भौगोलिक प्रतिबंध हटाए गए हैं, जिससे देशभर में सहकारी संस्थाओं तक वित्तीय सहायता पहुंचाना आसान होगा।

डीसी ने किया रामगढ़ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, इयूटी से नदारद मिले तीन डॉक्टर, वेतन पर लगी रोक

बिभा संवाददाता

रामगढ़: उपायुक्त ऋतुराज ने बुधवार को सदर अस्पताल रामगढ़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति, ओपीडी संचालन, साफ-सफाई, दवा एवं जांच की व्यवस्था सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के क्रम में तीन चिकित्सक-ईपनटी विशेषज्ञ डॉ. कीर्ति सिन्हा, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. राजन पांडे एवं डमेटीलॉजिस्ट डॉ. अजीत कुमार सिंह-अनुपस्थित पाए गए। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों चिकित्सकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के साथ अगले आदेश तक उनके वेतन पर रोक लगाने का



निर्देश दिया।

सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीजों के आने को देखते हुए उपायुक्त ने सिविल सर्जन रामगढ़ को आँखों, गायनो एवं मेडिसिन विभाग में प्रतिदिन दो ओपीडी संचालित कराने का निर्देश दिया,

ताकि मरीजों को बेहतर एवं सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें तथा उन्हें अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

उपायुक्त ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया तथा संबंधित

पदाधिकारियों को अस्पताल परिसर एवं सभी वाडों में नियमित रूप से बेहतर साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए सभी योग्य लाभकों को योजना से आच्छादित कर इसका लाभ

उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न वाडों में जाकर मरीजों से सीधे संवाद किया। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिल रही चिकित्सा सुविधाओं, दवाओं, जांच, भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली तथा उनकी समस्याओं से अवगत हुए।

इसके अलावा उपायुक्त ने सदर अस्पताल में संचालित सभी ओपीडी, लैब, रजिस्ट्रेशन काउंटर, शौचालय, मेस, अल्ट्रासाउंड रूम एवं एक्स-रे रूम सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों को होने वाली परेशानियों को दूर करने तथा अस्पताल की विभिन्न सेवाओं को सुव्यवस्थित एवं सुगम बनाने के निर्देश दिए।

मेस के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मरीजों को निर्धारित समय पर

भोजन उपलब्ध कराने तथा निर्धारित मेन्यू के अनुरूप ही गुणवत्तापूर्ण भोजन देने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को अस्पताल में मरीजों की सुविधा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि सदर अस्पताल जिले की प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाओं में से एक है और यहां आने वाले प्रत्येक मरीज को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं चिकित्सकों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने तथा मरीजों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

दिव्यांगजनों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल



बिभा संवाददाता

हजारीबाग: उपायुक्त हेमन्त सती के निदेशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले 25 पात्र लाभुकों के बीच बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इससे पूर्व जिला प्रशासन की पहल पर 50 दिव्यांग लाभुकों के बीच बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया जा चुका है। वहीं, गुरुवार को 25 अन्य पात्र दिव्यांग लाभुकों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया जाएगा। इस प्रकार चार चरणों में कुल 100 दिव्यांग लाभुकों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जा रही है।

वितरण के दौरान डीएसडब्ल्यूओ के कर्मियों द्वारा दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगों को दिव्यांग उपकरण उपलब्ध कराने हेतु जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा कराई गई प्रचार प्रसार के दौरान कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। आने वाले दिनों में जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त आवेदनों पर दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है।

उपायुक्त हेमन्त सती ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार

60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले 25 लाभुकों के बीच बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण

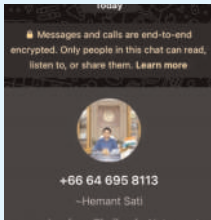
की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। दिव्यांगजनों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बैटरी चालित ट्राईसाइकिल से लाभुकों को अपने दैनिक कार्यों, शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक गतिविधियों में आने-जाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावों क्रियाचक्र से दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ उनके आत्मविश्वास को भी मजबूती मिलेगी। उपविकास आयुक्त रिया सिंह ने कहा कि बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दिव्यांगजनों के लिए केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर एवं समानजनक जीवन की ओर आगे बढ़ाने का माध्यम है। इससे विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने तथा कर्मकाजी लाभुकों को अपने कार्यस्थल तक आने-जाने में सुविधा मिलेगी।

संक्षिप्त खबरें

उपायुक्त के नाम एवं तस्वीर का दुरुपयोग कर बनाई गई फर्जी व्हाट्सएप आईडी, सतर्क रहने की अपील

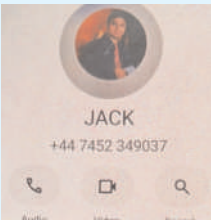
हजारीबाग(बिभा): उपायुक्त हजारीबाग के नाम एवं तस्वीर का दुरुपयोग कर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाई गई है। +66 646958113 नंबर से लोगों के पदाधिकारियों एवं अन्य लोगों से संपर्क किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त नंबर का उपायुक्त अथवा जिला प्रशासन से कोई संबंध नहीं है और यह साइबर ठगी का प्रयास है। मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को दे दी गई है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों, कर्मियों, जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि उक्त नंबर अथवा किसी अन्य संदिग्ध नंबर से प्राप्त संदेश, कॉल या धनराशि की मांग पर विश्वास न करें और कोई व्यक्तिगत अथवा वित्तीय जानकारी साझा न करें। संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाना अथवा साइबर पुलिस को दें। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने एवं किसी भी अनधिकृत संदेश की सत्यता की पुष्टि करने की अपील की है।



फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर दैनिक अखबार के डायरेक्टर के नाम व तस्वीर का दुरुपयोग

हजारीबाग(बिभा): दैनिक अखबार के डायरेक्टर हेमन्त कुमार के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग कर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाए जाने का मामला सामने आया है। फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए लोगों से संपर्क किए जाने की जानकारी मिलने के बाद हेमन्त कुमार ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। बताया गया कि किसी असामाजिक तत्व ने हेमन्त कुमार की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल तैयार की है। इस फर्जी आईडी से यदि किसी व्यक्ति को मैसेज, कॉल या किसी प्रकार की आर्थिक मदद अथवा अन्य मांग की जाती है, तो उस पर भरोसा नहीं करने की अपील की गई है। हेमन्त कुमार ने स्पष्ट किया है कि उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर बनाई गई उक्त व्हाट्सएप आईडी से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि ऐसे किसी भी संदिग्ध संदेश या कॉल का जवाब देने से पहले उसकी पूरी तरह पुष्टि कर लें। उन्होंने कहा कि फर्जी आईडी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से पैसे की मांग, बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, निजी दस्तावेज अथवा अन्य संवेदनशील जानकारी मांगी जा सकती है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की जानकारी साझा न करें और संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना संबंधित साइबर थाना या पुलिस को दें।



शिक्षा में एआई का बढ़ता प्रभाव: वैयक्तिकृत अधिगम, मूल्यांकन एवं नैतिकता का समन्वित परिप्रेक्ष्य : डॉ. मनोहर दास



हजारीबाग(बिभा) : एस.बी.एम. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग तथा श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हजारीबाग के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों द्वारा संयुक्त रूप से तथा शैक्षणिक सहयोगी आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग के सहयोग से ह्रउन्नत शिक्षण एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ अनुसंधानह्र विषय पर आधारित एक सप्ताहव्यापी व्याख्यानमाला कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम के अंतिम दिन अतिथि सह मुख्य वक्ता डॉ. मनोहर कुमार दास, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड, श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. समापित कुमार पाल, एस.बी.एम. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शशिकांत यादव ,दोनों महाविद्यालयों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों के समन्वयक श्री अमित सिंह एवं डॉ. परीक्षित लायक व्याख्यानमाला के समन्वयक डॉ. पंकज कुमार, डॉ. अपोलिना बाखला, डॉ. कल्पना प्रिया एवं डॉ. जीतू घोष, तथा दोनों महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानन्द जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

जनगणना-2027 की तैयारी शुरू, 'जिला जनगणना हस्तपुस्तिका' के लिए क्षेत्रीय कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित

बिभा संवाददाता

लातेहार। भारत की जनगणना-2027 के तहत 'जिला जनगणना हस्तपुस्तिका' (DCHB-2027) तैयार करने के उद्देश्य से विकास भवन स्थित उप विकास आयुक्त सभागार में क्षेत्रीय कर्मियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता और शुभारंभ जिले के उपायुक्त संदीप कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्याकी स्थिति का महत्वपूर्ण आधार है। उपायुक्त ने आंकड़ों के संकलन और सत्यापन में पूरी सावधानी, निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया,



ताकि तैयार होने वाली हस्तपुस्तिका विश्वसनीय और त्रुटिरहित हो। प्रशिक्षण के दौरान कर्मियों को जिला जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करने, आवश्यक सूचनाओं के संकलन, अभिलेखों के सत्यापन और प्रपत्रों में सटीक जानकारी दर्ज करने के तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा क्षेत्र भ्रमण के

दौरान आने वाली संभावित कठिनाइयों और उनके समाधान पर भी आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। इस कार्यक्रम में लातेहार, चंदवा और नगर पंचायत लातेहार क्षेत्र के जनसेवक, राजस्व उप निरीक्षक और पंचायत सचिव मुख्य रूप से शामिल हुए। मौके पर जिला योजना पदाधिकारी समीर कुर्लू, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. चंदन,

सीबीएसई ईस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट में श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल ने लहराया परचम

बिभा संवाददाता

रामगढ़: बी.एन. पब्लिक स्कूल, गोरखपुर में आयोजित सीबीएसई ईस्ट जोन हॉकी टूर्नामेंट में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल, रामगढ़ की तीनों हॉकी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का गौरव बढ़ाया। अंडर-14 बालिका एवं अंडर-17 बालिका टीम ने उपविजेता, जबकि अंडर-17 बालक टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर-14 बालिका टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल, अनुशासन और टीम भावना का परिचय देते हुए उपविजेता का गौरव हासिल किया। टीम में श्रेया कुमारी, इशिका कोर, राज नंदनी, पिऊ करमाकर, रुही पटेल, आराध्या गोस्वामी, रिंशिका कुमारी,सौम्या कुमारी, अंकिता आर्या, स्नेहल धनजी पवार, शैली खंडेलवाल, साक्षी कुमारी एवं सृष्टि आर्या शामिल रही। अंडर-17 बालक टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए तृतीय



स्थान हासिल किया। खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल, अनुशासन और संघर्षशील भावना से सभी को प्रभावित किया। टीम में हेमंत कुमार, गौरव चौधरी, सत्यजीत बेदिवा, आदर्श कुमार, कुमार सानू, समीर कुमार, अंश शर्मा, कुमार आदित्य, भरत कुमार, सुमित कुमार एवं दिव्यांश कुमार शामिल रहे। अंडर-17 बालिका टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल और संघर्षशील प्रदर्शन का परिचय देते हुए उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। टीम में रिया रानी, एंजेल राय, ऐलिन सोनी, राफिका नाज, शालू कुमारी, प्रसिद्धि पांडेय, हर्षा कुमारी, सुजाता कुमारी, अस्मिता पॉल, प्रियांशी

कुमारी वर्मा, रितिका बनर्जी एवं परी कुमारी शामिल रही। विद्यालय के प्राचार्य हरजाप सिंह ने तीनों टीमों की शानदार उपलब्धि पर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उनकी मेहनत, अनुशासन, टीम भावना और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेलों में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा। विद्यालय प्रबंधन की ओर से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान परमदीप सिंह कालरा तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के सम्माननीय सदस्य मनमोहन सिंह लांबा, हरपाल सिंह अरोड़ा, सरदार सुंदरपाल सिंह चंडोक, वरिंदर सिंह चंडोक, गुप्ती सिंह जॉली, नरेंद्र पाल सिंह गुजराल, पुष्पिंदर पाल सिंह, गुदीप सिंह सैनी, सतिंदर सिंह होरा, विक्रमजीत सिंह कोहली, गुप्तीत सिंह चाना, रमन बेदी एवं करमजीत सिंह जगनी ने खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई दी।

महिलाओं से संबंधित कानूनों पर पियर लीडर्स एवं पारा लीगल वालंटियर्स के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

बिभा संवाददाता

रामगढ़: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामगढ़ मो. तौफीकुल हसन के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार के तत्वावधान में कॉन्फ्रेंस हॉल व्यवहार न्यायाल में 90 दिवसीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं लड़कियों से संबंधित कानूनों, उनके विधिक अधिकारों तथा उपलब्ध विधिक सहायता के संबंध में पियर लीडर्स एवं पारा लीगल वालंटियर्स (लड़कियों एवं महिलाओं) के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पियर लीडर्स एवं पारा लीगल वालंटियर्स को महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों तथा उनके संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना एवं उन्हें समाज में जरूरतमंद महिलाओं तक विधिक जानकारी एवं सहायता पहुंचाने हेतु सक्षम बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों एवं प्रावधानों, जैसे घरेलू

हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सहित महिलाओं एवं बालिकाओं को प्राप्त विधिक अधिकारों एवं संरक्षण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को निःशुल्क विधिक सहायता,

जिला विधिक सेवा। प्राधिकार की भूमिका, पीड़ित महिलाओं के लिए उपलब्ध सहायता एवं संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, उत्पीड़न एवं भेदभाव की घटनाओं में पीड़ित को उचित विधिक सहायता एवं संबंधित प्राधिकार तक पहुंचाने में पारा लीगल वालंटियर्स की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार रामगढ़ के चीफ एल.ए.डी.सी सुजित कुमार सिंह, पारा लीगल वालंटियर्स, पियर लीडर्स एवं अन्य प्रतिभागी उपस्थित रहे।

धीरज प्रसाद साहू ने की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात, जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन पर हुई अहम चर्चा

बिभा संवाददाता

नई दिल्ली/लोहारदगा: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अहम बैठक में झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, पार्टी संगठन को मजबूत करने और राज्य में चल रहे खडरउ-खरउ अभियानों के आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

मुलाकात के दौरान धीरज साहू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को खडरउ-खरउ अभ्यर्थियों की मांगों और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस इन युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाए। इसके जवाब में खड़गे ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस अभ्यर्थियों के न्यायपूर्ण अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। पूर्व सांसद ने मल्लिकार्जुन खड़गे को झारखंड में होने वाली एक आगामी आमसभा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।

खड़गे ने इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि वे जल्द ही झारखंड का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर संगठन को नई ऊर्जा देंगे। बैठक में प्रदेश कांग्रेस संगठन को और अधिक धारदार बनाने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और भविष्य की राजनीतिक रणनीतियों पर भी सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ।



उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

असामाजिक हो रहे सोशल मीडिया का नियमन जरूरी



संपादकीय

पैलेट के जख्म

इसमें दो राय नहीं कि किसी आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के किन्हीं परिस्थितियों में उग्र होने और जन-धन की हानि रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन को कार्रवाई करनी होती है। इसमें भी दो राय नहीं है कि राज्य के पास हिंसा को रोकने और कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का भी है कि लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे विरोध को रोकने के लिए प्रयोग की गई ताकत का स्तर क्या रहा। जाहिर है राष्ट्रविरोधी ताकतों, हिंसक भीड़ तथा छात्रों के आंदोलन को एक ही तौर-तरीके से नहीं निपटा जा सकता है। इसी आलोक में सवाल पैदा होता है कि जंतर-मंतर से शुरू हुए संसद चलो मार्च को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई ताकत क्या जरूरी थी? क्या उचित तरीके से अधिकृत थी? ऐसा ही विवाद इस आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर खड़ा हुआ है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने शुरूआत से ही पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया। जबकि बाद में जनरल डायरी में यह दर्ज किया गया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने एंटी-रायट गन से दो राउंड फायरिंग की थी। वहीं दूसरी ओर छात्र प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। खासकर, कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष ने गृह मंत्री पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तीखे प्रहार किए हैं। वे बाकायदा गृह मंत्री के इस्तीफे को लेकर लगातार अभियान चलाते रहे हैं। इसी बीच सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली के दो अस्पतालों से एक्जत्र की गई जानकारी के अनुसार बीस जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम दस लोगों को पैलेट गन से चोट लगी थी। इन अस्पतालों में पैलेट गन से आहत छात्रों ने उपचार कराया था। निस्संदेह, पैलेट गन से घायल होने वालों का यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है, न कि किसी बिना पुष्टि वाले दावों पर आधारित है। दरअसल, पैलेट गन की जद में आये छात्रों के अनुभव पेशान करने वाले रहे हैं। खबरों के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारियों के घेरेों, छाती और आंखों पर चोट आई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि एक छात्र की आंख की रोशनी भी जा सकती है। सार्वजनिक विमर्श में सवाल उठाये जाते रहे हैं कि छात्र आंदोलनकारियों के विरुद्ध पैलेट गन का इस्तेमाल करने का तार्किक आधार क्या है। वहीं दूसरी ओर कानून-व्यवस्था बनाये रखने के दौरान मेटल पैलेट गन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि मौजूदा नियमों के तहत विशेष परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

चिंतन-मनन

जो नहीं है उसे पाना हो ध्येय

असंतुष्ट होने का अर्थ दुखी होना नहीं है। असल में कोई आदमी पूरी तरह सुखी होकर भी असंतुष्ट हो सकता है। सुखी होने का मतलब है, जो है, उसे आनंद से भोगना। और असंतुष्ट होने का अर्थ है: जो नहीं है उसे आनंद से पैदा करने का श्रम करना। जब अधिकतम लोग समाज में इस भाति श्रम करते हैं तो समाज संपन्न और समृद्ध होता है। और जब अधिक लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है बस ठीक है, वही रुक जाना है, तो फिर पूरा समाज धीरे-धीरे दरिद्र हो जाता है। जिंदगी का सारा विकास, जो नहीं है, उसे पाने की ही होता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि ऐसा किसी जगह मानने की जरूरत नहीं है कि अब सब पूरा हो गया, अब भला मुझे क्या करना है ! यह मरने के ढंग है। यह अपने भीतर जिंदा रहते हुए मर जाना है। जब तक श्वास है, तब तक एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि मेरी तो सच में ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो गईं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को दूसरों की आवश्यकताएं पूरा करने में लग जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पक्का ऐसा लगता है कि मेरी तो सभी आवश्यकताएं पूरी हो गईं, मैं क्यों श्रम करूँ? तो उसे चारों तरफ देखना चाहिए कि अब मेरा काम तो जमीन पर खस हो गया, लेकिन दूसरों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं, उनके लिए मैं श्रम करने में लग जाऊं। लेकिन श्रम से नहीं बचा जा सकता। आपकी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, तो अपने चारों तरफ देखिए। बहुत लोगों की पूरी नहीं हुई हैं, अतः उनके लिए श्रम करने में लग जाइए। लेकिन खाली बैठने का हक किसी को नहीं है। संन्यासी को भी खाली बैठने का हक नहीं है। देश को संपन्न करना है तो सभी को श्रम में लगना ही चाहिए। और श्रम में हम तभी लगेगे जब कोई आवश्यकता पूरी करनी हो। चाहे अपनी, चाहे किसी दूसरे की, लेकिन आवश्यकता पूरी करने की दौड़ जारी रहनी चाहिए। यह दौड़ शांत हो, यह दौड़ बहुत आनंदपूर्ण होनी चाहिए, यह दौड़ पागल की नहीं होनी चाहिए, विशिप्त की नहीं होनी चाहिए। यह दौड़ नींद को हराम कर देने वाली नहीं होनी चाहिए। यह दौड़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आदमी बिल्कुल होश खो दे और दौड़ता रहे, और उसे पता भी न पने कि कहाँ दौड़ रहा है। यह दौड़ बहुत आनंदपूर्ण होनी चाहिए, यह दौड़ बहुत शांत होनी चाहिए, यह दौड़ बहुत स्वस्थ होनी चाहिए। यह हो सकती है। लेकिन हमने इस तरफ सोचा नहीं

दिल्ली में बीस जुलाई को काकोरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा और 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के जेन जी के संबोधन की वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत चर्चा में हैं। चर्चा से ज्यादा उनकी भूमिका कहीं ज्यादा विमर्श के केंद्र में है। इसमें दो राय नहीं कि दुनियाभर में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रचलन में हैं, उनमें से ज्यादातर विदेशी हैं। जाहिर है कि वे उन जगहों के कानूनों और सांस्कृतिक परंपराओं से ज्यादा संचालित हैं, जहां उनके मुख्यालय हैं। इसलिए अपने व्यापक हितों के लिए वे अपने प्रचलन वाले देशों की परंपराओं और संस्कृतियों को सवालों के घेरे में लाने, उसका उपहास उड़ाने और उन्हें तार-तार करने वाला अलगोरिदम उन्होंने विकसित कर रखा है। जिसका खामियाजा तीसरी दुनिया के देश और वहां की सांस्कृतिक परंपराएं उठा रही हैं। सोशल मीडिया को लोकतंत्र के बड़े मंच के रूप में 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिशिया के सिटी बौजिज शहर में फलों का ठेला लगाने वाले मोहम्मद बोआजीजी की आत्महत्या के बाद हुए उबाल के बाद देखा जाने लगा। म्यूनिसिपल कर्मचारियों की सख्ती के चलते शुद्ध बोआजीजी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। किसी ने इस घटना को सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया के तत्कालीन अलगोरिदम ने इस घटना को इस रूप में प्रस्तुत किया कि समूचे अरब जगत में उबाल आ गया। नागरिक अधिकारों की स्थापना और लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर अरब देशों की जनता सड़कों पर उतर आई। इसका ही नतीजा मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक पर दिखा। जहां महीनों तक लोग जमे रहे और वहां के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। यह आग सीरिया, यमन और लीबिया तक जा पहुंची। वहां के पारंपरिक शासकों के खिलाफ लोगों का दबा हुआ गुस्सा निकला और कई जगह सत्ताएं बदल गईं। भारत में भी इसके ही कुछ महीनों के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। यह आग सीरिया, यमन और लीबिया तक जा पहुंची। वहां के पारंपरिक शासकों के खिलाफ लोगों का दबा हुआ गुस्सा निकला और कई जगह सत्ताएं बदल गईं। भारत में भी इसके ही कुछ महीनों से आहत छात्रों को आगे रखकर एक आंदोलन छेड़ा गया। जिसकी परिणति आम आदमी पार्टी के रूप में हुई और वह दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। फिर पंजाब में भी उसने पैठ बना ली।

इन घटनाओं को याद करना इसलिए जरूरी है कि इन सबके पीछे सोशल मीडिया के जरिए त्वरित गति से फैलाई गई सूचनाओं का हाथ सबसे ज्यादा रहा। तब सोशल



मीडिया को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया गया। सोशल मीडिया के बारे में कहा गया कि लोकतंत्र में सबकी आवाज पहुंचाने और उन्हें मौका देने का यह बड़ा माध्यम है। इसे लोकतंत्र के वाजिब और जरूरी औजार के रूप में भी मान्यता मिली। लेकिन बीतते वक्त के साथ पता चल रहा है कि जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, वह लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा अनसोशल यानी असामाजिक भी है। यह ठीक है कि सोशल मीडिया के जरिए व्यवस्था की अंधी सुरंग में खो रही आवाजों को मौका मिलता है। लेकिन यह उतना ही सच है कि इस माध्यम ने लोगों की नजर का पानी उतार दिया है। लोग अब लिहाज करना भूल गए हैं। सोशल मीडिया पर अगर किसी की बात पसंद नहीं आती तो उसे खुलेआम गालियां दी जा सकती हैं। उसके चरित्र पर आक्षेप लगाया जा सकता है। उसका चरित्र हनन किया जा सकता है। चाहे वह व्यक्ति सामाजिक जीवन में कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न हो, उसकी उम्र चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो।

सोशल मीडिया मंचों ने अपना अलगोरिदम भी ऐसा विकसित किया है, जो अच्छी बातों, सामाजिक चिंतन और बेहतर कल की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देखा। एक तरह से कहें तो वह इसकी अनदेखी ही करता है। लेकिन

अंगदान की संस्कृति ही मानवता को नई दिशा दे सकती है

महान त्याग की परंपरा बहुत पुरानी है। महर्षि दधीचि की कथा इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। पौराणिक परंपरा के अनुसार जब देवताओं को असुरों से संघर्ष के लिए ऐसे अस्त्र की आवश्यकता हुई जिसे दधीचि की अस्थियों से बनाया जा सके, तब महर्षि दधीचि ने लोककल्याण के लिए अपना शरीर ही त्याग दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया और उससे जनकल्याण की रक्षा हुई। यह कथा आधुनिक अर्थों में अंगदान की चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अपने शरीर को भी समाज और सुष्टि के कल्याण के लिए समर्पित कर देने की भारतीय त्याग-चेतना का अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक अवश्य है। भारत के राष्ट्रपति सचिवालय ने भी अंग एवं देहदान की भारतीय परंपरा को समझाते हुए महर्षि दधीचि के इस प्रसंग का उल्लेख किया है। हमारी परंपरा में राजा शिवि की कथा भी त्याग और जीव-दया की अद्भुत मिसाल है। एक कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस तक देने की तत्परता दिखाई। चाहे ये प्रसंग धार्मिक आख्यान हों, लेकिन इनके भीतर छिपा संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है-अपने जीवन और शरीर को केवल अपनी निजी संपत्ति न समझना, बल्कि उसे व्यापक जीवन के कल्याण से जोड़ना। जैन दर्शन का सूत्र ह्यपरस्पोरपहो जीवानाम्ह भी यही बताता है कि जीव एक-दूसरे के उपकार के लिए हैं। अंगदान इस विचार का आधुनिक वैज्ञानिक रूप कहा जा सकता है।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इस मानवीय भावना को वास्तविक जीवन बचाने की शक्ति प्रदान कर दी है। वर्ष 1954 में दुनिया का पहला सफल मानव किडनी प्रत्यारोपण हुआ। रोनाल्ड ली हेरिक ने अपनी एक किडनी अपने जुड़वां भाई रिचर्ड को दान की थी। यह घटना चिकित्सा इतिहास में एक ऐसी क्रांति की शुरूआत बनी, जिसने आगे चलकर अंग प्रत्यारोपण को लाखों लोगों के लिए जीवन की आशा बना दिया। इसके बाद 1967 में मानव हृदय प्रत्यारोपण की

सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि चिकित्सा विज्ञान मनुष्य की मृत्यु और जीवन के बीच खड़ी कई दीवारों को तोड़ सकता है। भारत ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय यात्रा की है। देश में पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण 1 दिसंबर 1971 को चेन्नई के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लूर में हुआ था। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन भारत में हजारों लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण जीवन का नया द्वार बनेगा। आज चिकित्सा तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किडनी, लिवर, हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय और आंत जैसे अंगों के साथ कॉर्निया, त्वचा, हड्डी और हृदय वाल्व जैसे ऊतकों का भी प्रत्यारोपण संभव है।

लेकिन विज्ञान की क्षमता जितनी बड़ी है, हमारी सामाजिक चेतना उस गति से नहीं बढ़ पाई। यही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में आज भी प्रत्यारोपण की आवश्यकता और उपलब्ध अंगों के बीच बड़ा अंतर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2024 में देश में अंग प्रत्यारोपण की गतिविधि व्यापक रही, लेकिन मृतक दाताओं की संख्या अभी भी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ साफ है-हमारे अस्पतालों में तकनीक है, डॉक्टर हैं, सर्जरी की क्षमता है, लेकिन जीवन बचाने के लिए पर्याप्त अंग नहीं हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें अंगदान की मृत्यु की चर्चा नहीं, जीवन की चर्चा बनाना होगा। परिवारों में इस विषय पर समय रहते बातचीत होनी चाहिए। स्कूलों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और मीडिया को मिलकर ऐसी वातावरण-निर्मिति करनी होगी जिसमें अंगदान सुनते ही भय नहीं, बल्कि करुणा और जीवन बचाने का भाव पैदा हो। आज भी अनेक लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर को क्षति पहुंचाना धर्म के विरुद्ध है। कुछ लोगों को अगले जन्म की चिंता होती है, कुछ को शरीर के साथ होने वाली चिकित्सा प्रक्रिया का भय होता है और कुछ परिवार अंतिम समय में

जंतर मंतर-रांची: छात्र आंदोलन एक रूप अनेक

बी जहाँ आंदोलनस्थल पर अनेक स्वयंसेवी लंगर चला रहे हैं व आंदोलनकारी छात्रों के दूर दराज बैठे समर्थक फूड ऐप्स के जरिए छोटे आंदोलन स्थल पर भोजन आँदर कर रहे हैं साथी को भेडिकल व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ भी भोजन इतनी अधिक मात्रा में आ रहा है कि आंदोलनकारी छात्रों ने वीडियो जारी कर लोगों से कुछ दिन आँदर रोकने की अपील की ताकि छात्रों को दान की थी। यह बचे हुए भोजन को जरूरतमंदों में बांटा जा सके। इसके अलावा रांची के स्थानीय दुकानदारों और आम नागरिकों द्वारा आंदोलन स्थल पर भोजन,समोसे, बिरयानी,नाश्ता और पानी आदि पहुंचाया जा रहा है। अनशन पर बैठे छात्र नेताओं की सेहत की देखभाल के लिए रांची के सदर अस्पताल में मेडिकल टीम नियमित रूप से आंदोलन स्थल पर पहुंचकर स्वास्थ्य जांच (ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल) कर रही है। इसके अतिरिक्त झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने निर्देश जारी किया है कि आंदोलन के दौरान बीमार या चोटिल होने वाले छात्रों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, चाहे वे सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं या निजी अस्पताल में। परन्तु इन दोनों अर्थात दिल्ली व रांची के आंदोलन में जो सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है वह है जंतर मंतर के छात्र आंदोलन का विरोध करने वालों का रांची के आंदोलन में बढ़चढ़कर हिस्सा लेना। बड़ी हैरत की बात है कि जो वर्ग,जो संगठन और जिस विचारधारा से जुड़े लोग जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को देशद्रोही, बदतमीज, गटर जनेरेशन,गलियां बोलेने व अपशब्द इस्तेमाल करने वालों का झुण्ड,विदेशी फंडिंग से चलने वाला आंदोलन बता रहे थे, दिल्ली के आंदोलन में जो लोग

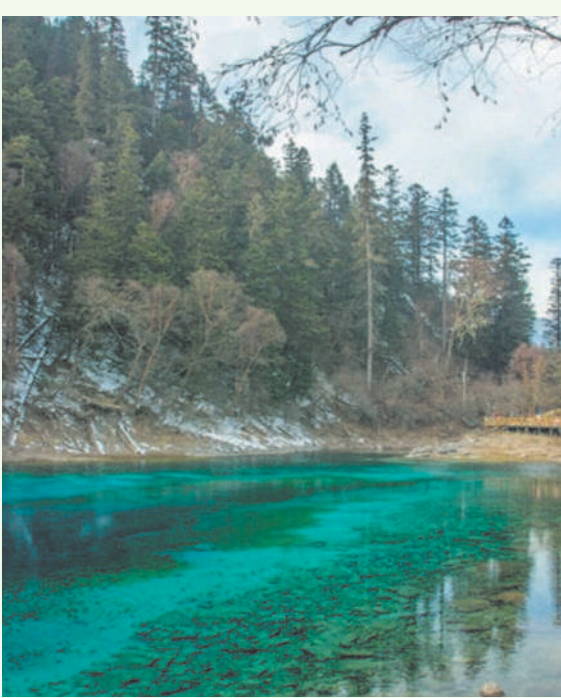
हिन्दू-मुस्लिम का दृष्टिकोण दृढ़ रहे थे,जिन्हें दिल्ली के आंदोलन कारी आवारा व चरित्रहीन नजर आ रहे थे वही लोग वही वर्ग और वही विचारधारा रांची के छात्र आंदोलन में कुछ इसतरह बढ़चढ़कर हिस्सा लेने को उतावली है। गोया रांची का आंदोलन छात्र आंदोलन के बजाये देश का दूसरा स्वाधीनता संग्राम हो? याद कीजिये कि जंतर मंतर आंदोलन के संदर्भ में ही एक हिंदुत्व विचार और करल भाजपा के बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रमुख टीजी मोहनदास ने कहा था कि अगर स्थिति उनके नियंत्रण में होती, तो वे नई दिल्ली के आंदोलन स्थल के आसपास कर्फ्यू लगाकर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा देते। इस व्यक्ति ने प्रदर्शन में शामिल धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी विचारधारा वाली छात्राओं व महिलाओं के साथ रेप करवाने जैसी बेहद अमर्यादित और अपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थीं। साथ ही गोदी मीडिया के नाम से बदनाम सत्ता का पिछलग्गू मीडिया भी जो जंतर मंतर आंदोलन से या तो मुंह मोड़े हुआ था या इसी आंदोलन विरोधी वर्ग की तरह आंदोलन में केवल नकारात्मकता तलाश रहा था,जिसे संसद भवन के पास चल रहा इतना बड़ा छात्र आंदोलन नजर नहीं आ रहा था वही मीडिया रांची में डेरा जमाये हुये है और अपने तरीके से छात्र आंदोलन का नरेटिव सेट करने में लगा है। इस दोहेपन का केवल एक ही कारण है कि दिल्ली में केंद्र व दिल्ली राज्य, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जबकि झारखण्ड में झारखंड मुक्ति मोर्चा , कांग्रेस और राष्टीय जनता दल, के गठबंधन यानी इण्डिया गठबंधन की सरकार है और झामुमो के हेमंत सोरेन इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं। इसलिये इनका समर्थन छात्र आंदोलन को नहीं बल्कि यह झारखण्ड में

औसतन 57 प्रतिशत लोगों ने माना कि सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन इसे बिनाशकारी मानने वालों की संख्या भी कम नहीं रही। करीब 35 प्रतिशत से ज्यादा लोगों का का कहना था कि सोशल मीडिया बिनाशकारी साबित हो रहा है। सिर्फ 34 प्रतिशत अमेरिकियों ने ही सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए लाभकारी माना, जबकि 64 फीसद का कहना था कि इसने नकारात्मक प्रभाव ज्यादा डाला है। हाल ही में जेन जी से चर्चा के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी सोशल मीडिया को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उसमें उन्होंने कहा है कि यदि सोशल मीडिया पर उनके कारण दस लाख लोग कोई गलत निर्णय लेते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। सोशल मीडिया पर सकारात्मक, उपयोगी और समाजहित की सामग्री साझा करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर केवल प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। जेन-जी में भी यह विवेक विकसित होना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। वरिष्ठ पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है कि वह नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करे तथा उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझाएं।

सोशल मीडिया का अनसोशल चेहरा और मंच आर्थिक कमाई का जरिया भी है। नंगई, हिंसा, और व्यक्तिवार-अतिचार के कहानियाँ, हृश्य, वीडियो और फोटो को वायरल करने में उसका कोई सानी नहीं है। इस बहाने इसे प्रसारित करने वाले को सोशल मीडिया मंच आर्थिक कमाई भी कराते हैं। और तो और, वे खुद भी ऐसी घटनाओं, हृष्यों को प्रसारित-प्रचारित और वायरल करने के लिए बड़ी रकम लेते हैं। संसदीय समिति के सामने फेसबुक और इंस्टाग्राम की संचालक कंपनी मेटा के अधिकारियों ने माना है कि काकोरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान गाली, हिंसा आदि को मुखाटे के पीछे से दखल भी दे रहे हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती भी दे रहे हैं। वक्त आ गया है कि इनके नियमन के लिए कठोर कानून बनाए जाएं। जिसके तहत उन्हें अभिव्यक्ति के अधिकार को बढ़ावा देने की व्यवस्था तो हो, लेकिन इसकी आड़ में अराजकता फैलाने की छूट नहीं।

मानसिक रूप से इतने टूट जाते हैं कि अंगदान का निर्णय नहीं ले पाते। इन भ्रमों का समाधान टकराव से नहीं, संवाद, संवेदना और वैज्ञानिक जानकारी से होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी होगी कि अंगदान किसी पर थोपा जाने वाला धार्मिक या सामाजिक कर्तव्य नहीं है। यह एक स्वेच्छिक, नैतिक और मानवीय निर्णय है, जिसे व्यक्ति को विश्वसनीय चिकित्सा एवं कानूनी जानकारी के आधार पर लेना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छ से यह संकल्प करता है कि मृत्यु के बाद उसके उपयोगी अंग किसी जरूरतमंद को मिलें, तो वह अपने जीवन की अंतिम घड़ी को भी मानवता के उत्सव में बदल सकता है। भारत में अंगदान की प्रेरक घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में नागपुर में 52 वर्षीय शिक्षक कोंडवा दत्तात्रेय मडावी मृतक अंगदान करने वाले 200वें दाता बने, उनके अंगों से तीन लोगों को नया जीवन मिला। ऐसी घटनाएँ हमें बताती हैं कि अंगदान कोई दूर की आदर्शवादी कल्पना नहीं, बल्कि हमारे आसपास घटने वाली वास्तविक जीवन-बचाने वाली प्रक्रिया है। दिल्ली में 70 वर्षीय मृत महिला के गुर्दे का सफल उपयोग कर एक 56 वर्षीय महिला को जीवन की नई उम्मीद मिली-यह घटना यह भी बताती है कि केवल उम्र के आधार पर किसी संभावित दाता के अंगों को अनुपयोगी मान लेना उचित नहीं है, अंतिम निर्णय चिकित्सा स्थिति पर निर्भर करता है। भारत के कुछ राज्यों ने इस दिशा में उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तेलंगाना में 2024 में मृतक अंगदान की दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक रही और उसके हज्जीवदानह कार्यक्रम के माध्यम से हजारों प्रत्यारोपण संभव हुए। तमिलनाडु में भी मृतक अंगदान की व्यवस्था ने अनेक परिवारों को प्रेरित किया हैय 2026 में एक परिवार ने भाषा की बाधा के बावजूद डिजिटल अनुवाद की मदद से अपने प्रियजन के अंगदान का निर्णय लिया और अनेक मरीजों को जीवन मिला।

इण्डिया गठबंधन की सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस अवसरवादी विचारधारा का विरोध करने वालों का चेहरा रांची में उस समय भी बेनकाब हुआ जबकि जंतर मंतर के आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा और वहां अनशन पर बैठने वाली अखिल भारतीय छात्र संगठन AISA की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा जब हजारों छात्रों के साथ विधानसभा के लिये मार्च निकाल रही थीं उस समय एक युवक ने नेहा पर स्याही फेंक कर छात्र आंदोलन को समर्थन देने की अपनी हक़ीकत को उजागर कर दिया। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। नेहा बोरा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसके पास तर्क या बहस की क्षमता नहीं होती, वे ऐसी हक़त पर उतर आते हैं। उन्होंने इस हमले के पीछे भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि नेहा बोरा व उनका संगठन अखिल भारतीय छात्र संगठन AISA जंतर मंतर के आंदोलन में भी शामिल था और उसी उत्साह के साथ रांची में भी सक्रिय है। जबकि रांची में छात्र आंदोलन का मुख्य चेहरा बनने की इच्छा पालने वाले लोग जंतर मंतर में न केवल लापता थे बल्कि उनके विरोध में भी खड़े थे। व कहा जा सकता है कि जंतर मंतर व रांची दोनों जगह छात्र आंदोलन व उनकी मांग व समस्याएँ तो लगभग एक हैं परन्तु उनके अनेक रूप देखे जा रहे हैं। (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)



भारत की ये झीलें जन्नत से नहीं है कम, इस गर्मी ट्रेवल बकेट लिस्ट में करें शामिल
अगर आप भी इस गर्मी देश की फेमस और खूबसूरत झीलों को देखने का मन बना रहे हैं, तो आज हम आपको देश की कुछ अद्भुत और बेहद खूबसूरत झीलों के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर जाकर आप अपनी छुट्टियों को खास बना सकते हैं।

गर्मियों के मौसम में लगभग हर कोई ठंडी जगहों या समुद्र तटीय क्षेत्रों पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा इस मौसम में झीलों का नजारा भी देखने लायक होता है। ठंडी-ठंडी हवाओं के बीच झीलों को देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे में अगर आप भी इस गर्मी देश की फेमस और खूबसूरत झीलों को देखने का मन बना रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। क्योंकि आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको देश की कुछ अद्भुत और बेहद खूबसूरत झीलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर जाकर आप अपनी छुट्टियों को खास बना सकते हैं।

बड़ी लेक

राजस्थान के माउंट आबू में मीठे पानी की एक विशाल झील है। इसको बड़ी लेक के नाम से भी जाना जाता है। गर्मियों में यहां का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। बताया जाता है कि बड़ी लेक को खुद भगवान ने बनाया था। हर साल यहां पर बड़ी संख्या में लोग अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए आते हैं।

नैनी झील

नैनीताल के लोगों के लिए नैनी झील काफी ज्यादा फेमस है। नैनी झील को नैनीताल झील के नाम से भी जाना जाता है। नैनी झील में आप नौकायन यानी की नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। हर साल यहां पर देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं।

हुसैन सागर झील

वहीं हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, जोकि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। बताया जाता है कि इस हुसैन झील के तट पर गोलकुंडा और मुगलों के बीच संधि हुई थी। इसके साथ ही इस लेक में बुद्ध देवता की विशाल मूर्ति है। गर्मियों में हुसैन सागर झील का नजारा देखने लायक होता है।

लोकटक झील

लोकटक झील मणिपुर में है और यह झील पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा फेमस है। इस झील को प्लोटिंग झील के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि लोकटक झील दुनिया की इकलौती ऐसी लेक है, जोकि तैरती हुई दिखाई देती है। ऐसे में अगर आप गर्मियों में मणिपुर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको एक बार लोकटक झील देखने जरूर जाना चाहिए।

टारसर झील

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में टारसर झील मौजूद है, जोकि काफी ज्यादा खूबसूरत है। यह झील पर्वतीय इलाके में जमीन से करीब 3,795 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टारसर झील के आसपास बड़े-बड़े पहाड़ हैं, जोकि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं।



प्रकृति, इतिहास और आध्यात्म का अद्भुत संगम है शिवपुरी

शिवपुरी का नाम भगवान शिव के नाम पर पड़ा है। यह नगर कभी नरवर रियासत का हिस्सा था और बाद में ग्वालियर राज्य के अधीन आ गया। सिंधिया राजवंश ने यहाँ कई महलों, उद्यानों और स्मारकों का निर्माण करवाया, जो आज भी उसकी राजसी मय्यता की गवाही देते हैं।

शिवपुरी मध्य प्रदेश का एक सुरम्य और ऐतिहासिक नगर है, जो अपनी हरियाली, प्राचीन स्मारकों, राजसी विरासत और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह नगर एक समय में सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है और आज यह पर्यटकों के लिए एक शांत, सुंदर और विविध अनुभव प्रदान करता है।

शिवपुरी का ऐतिहासिक परिचय

शिवपुरी का नाम भगवान शिव के नाम पर पड़ा है। यह नगर कभी नरवर रियासत का हिस्सा था और बाद में ग्वालियर राज्य के अधीन आ गया। सिंधिया राजवंश ने यहाँ कई महलों, उद्यानों और स्मारकों का निर्माण करवाया, जो आज भी उसकी राजसी भव्यता की गवाही देते हैं।

शिवपुरी के प्रमुख दर्शनीय स्थल

1. माधव राष्ट्रीय उद्यान

शिवपुरी का सबसे प्रसिद्ध स्थल। यह राष्ट्रीय

उद्यान कभी सिंधिया राजाओं का शिकार क्षेत्र हुआ करता था। अब यह बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ, और अनेक पक्षियों का निवास स्थान है। यह प्रकृति प्रेमियों और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग है।

2. सिंधिया की छतरियाँ

सिंधिया राजाओं और रानियों की याद में बने ये संगमरमर के स्मारक भारतीय और मुगल वास्तुकला के सुंदर मिश्रण का उदाहरण हैं। यहाँ की कलाकृति, मेहराबों और जालीदार खिड़कियों देखने योग्य हैं।

3. माधव विलास महल

यह एक भव्य शाही महल है, जहाँ सिंधिया परिवार गर्मियों में रहा करता था। ऊँचाई पर स्थित यह महल अपने बगीचों, झरोखों और शाही वातावरण के लिए प्रसिद्ध है।

4. सागर तालाब और भंदेया कुंड

शिवपुरी के यह जल स्रोत प्राकृतिक सौंदर्य के

साथ-साथ स्थानीय लोगों की आस्था से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ बैठकर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं।

5. नरवर किला

शिवपुरी से लगभग 40 किमी दूर स्थित यह प्राचीन किला 10वीं शताब्दी में बना था और चंदेल, परमार, तोमर, और मुगलों के अधीन रहा। किले से आसपास का मनोरम दृश्य दिखाई देता है।

धार्मिक स्थल

सिद्धेश्वर महादेव मंदिर – एक प्राचीन शिव मंदिर जो स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत पूजनीय है।

छत्री मंदिर परिसर – यहाँ भगवान विष्णु और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियाँ स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण हैं।

क्या करें?

वन सफारी – माधव राष्ट्रीय उद्यान में सुबह या शाम की सफारी जरूर लें।

फोटोग्राफी – प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम आपको कैमरे से दूर नहीं रहने देगा।

स्थानीय भोजन – यहाँ का पारंपरिक मालवी और बुंदेली खाना जरूर चखें।

कैसे पहुँचें?

निकटतम रेलवे स्टेशन- शिवपुरी रेलवे स्टेशन, ग्वालियर (110 किमी)

निकटतम हवाई अड्डा- ग्वालियर

सड़क मार्ग- ग्वालियर, झाँसी, भोपाल और इंदौर से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है

ठहरने की व्यवस्था

शिवपुरी में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित रिसॉर्ट्स, लॉज और कई निजी होटल उपलब्ध हैं। यदि आप प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास रिसॉर्ट एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।

यात्रा का सर्वोत्तम समय

अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम शिवपुरी घूमने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस समय तापमान सुखद होता है और वन्यजीव भी अधिक दिखते हैं। शिवपुरी एक ऐसा स्थल है जहाँ इतिहास के पदचिह्न, राजसी भव्यता, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति— सब एक साथ मिलते हैं। यह पर्यटन के शोरगुल से दूर, आत्मिक और सुकून भरी यात्रा के लिए आदर्श स्थल है। यदि आप मध्य प्रदेश की अनदेखी विरासत को महसूस करना चाहते हैं, तो शिवपुरी की यात्रा जरूर करें।

खूबसूरत तैमारा घाटी का खौफनाक रहस्य, यहां आते ही बदल जाता है मोबाइल का वक्त



झारखंड की खूबसूरत जगहों के बीच तैमारा घाटी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। तैमारा घाटी झारखंड में %मौत

का हाइवे% के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आज हम आपको तैमारा घाटी की डरावनी कहानियों के बारे में बताने जा रहे

हैं। झारखंड भारत का एक प्रमुख और खूबसूरत राज्य है। यह राज्य साल 2000 में बिहार से अलग होकर देश का 28वां राज्य

बना था। आज झारखंड पूरे भारत का एक खनिज समृद्ध राज्य माना जाता है। झारखंड घने जंगलों, कोयला खदानों और बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। झारखंड की पतरानू घाटी, हुंडरू, टैगोर हिल और दशम वॉटरफॉल, नेतरहाट और तोपचांची झील जैसी खूबसूरत जगहों के बारे में हर कोई जानता है।

इन खूबसूरत जगहों के बीच तैमारा घाटी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। तैमारा घाटी झारखंड में %मौत का हाइवे% के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको तैमारा घाटी की डरावनी कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं।

तैमारा घाटी

तैमारा घाटी एक डरावनी जगह मानी जाती है, जोकि रांची-जमशेदपुर हाईवे यानी एनएच-33 पर है। यह जगह राजधानी रांची से करीब 30 किमी की दूरी पर है। हाइवे पर होने के कारण तैमारा घाटी को %मौत का हाइवे% के नाम से भी जानी जाती

है। यह हाइवे घने जंगलों के बीच में है, जिसकी वजह से यह काफी डरावना लगता है।

तैमारा घाटी की घटनाएं

तैमारा घाटी की एक नहीं बल्कि कई घटनाएं प्रचलित हैं। यह घाटी देखने में तो काफी मनमोहक लगती है। लेकिन यह घाटी कई मौतों की गवाह भी बन चुकी है। बताया जाता है कि इस घाटी गुजरने पर टाइम और तारीख अपने आप बदल जाती है।

तैमारा घाटी को लेकर एक अन्य कहानी है कि जंगलों के बीच से जब गाड़ी गुजरती है, तो उस गाड़ी की स्पीड मीटर खुद ब खुद बदल जाती है। वहीं माना जाता है कि रात के समय इस घाटी से अजीबो-गरीब आवाजें आती रहती हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि डर के कारण लोग रात में अकेले इस घाटी से गुजरना नहीं चाहते हैं।

तैमारा घाटी की डरावनी कहानियां

इस घाटी की सबसे डरावनी कहानियों में फेमस कहानी मोबाइल में डेट और समय का

बदल जाना है। कई लोगों का इस घाटी के बारे में मानना है कि जब कोई यहां से गुजरता है तो उसके मोबाइल में साल, डेट और समय अपने आप बदल जाता है।

ऐसा होने के पीछे लोग कुछ और कहानी भी बताते हैं। लोगों का मानना है कि तैमारा घाटी से कुछ ही दूरी पर मैग्नेटाइज्ड रॉक है। जिसकी वजह से यह समस्या होती है। वहीं एक अन्य कारण यह भी है कि इसी घाटी से कर्क रेखा गुजरती है, जिस वजह से यह समस्या होती है।

तैमारा घाटी घूमने जाते हैं पर्यटक

बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची से करीब 30 किमी दूर स्थित तैमारा घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां पर भीषण गर्मी में भी ठंडी-ठंडी हवाएं चलती हैं। ऐसे में पर्यटक भी तैमारा घाटी घूमने के लिए पहुंचते हैं। मानसून के समय पर्यटक दूर-दूर से यहां पर लॉन्ग ड्राइव के लिए पहुंचते हैं। मानसून में इस घाटी की खूबसूरती देखने लायक होती है।

मणिपुर के कांगपोकपी में नागा गांव पर हमला, नौ मकान जलाए

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हथियारबंद बदमाशों ने एक नागा गांव पर हमला कर कई मकानों में आग लगा दी। सुत्रों के अनुसार, लियांगमाई नागा समुदाय के कम से कम नौ मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना मंगलवार रात करीब 9-30 बजे टोकपा लियांगमाई गांव में हुई। टोकपा लियांगमाई गांव महिका और लोअर थानबा गांवों के बीच स्थित है। देर रात हुए हमले में नौ मकानों के पूरी तरह जलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, हमले के पीछे की परिस्थितियों और इसमें शामिल लोगों की पहचान तत्काल स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना के बाद गांव में भय और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की तत्काल जांच कराने और क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बुधवार सुबह तक कांगपोकपी जिला प्रशासन, मणिपुर पुलिस या सुरक्षा बलों की ओर से घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि हमले में किसी व्यक्ति की मौत या घायल होने की सूचना है या नहीं। मणिपुर के कई हिस्सों में पहले से जारी तनाव के बीच इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु जेल में छापा मारा, रेवन्ना व दो कैदियों के पास मिले फोन

बेंगलुरु (एजेंसी)। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु स्थित परप्पना अग्रहारा जेल में छापेमारी की। छापेमारी में जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रचलत रेवन्ना और प्रताप राय नाम के एक अन्य कैदी के पास फोन मिले हैं। दोनों के खिलाफ परप्पना अग्रहारा जेल में प्रिंजन्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा जेल के अंदर या बाहर गैर-कानूनी सामान लाने, बिना इजाजत कैदियों से बात करने या इन नियमों को तोड़ने में मदद करने पर सजा का प्रावधान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच अधिकारी नोटिस भेजने और आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले वे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और और जानकारी जुटा रहे हैं। डीजीपी जेल ने बताया कि मंगलवार दोपहर सीसीबी ने सभी हार्ड-प्रोफाइल कैदियों के यहां छापेमारी की। प्रज्वल रेवन्ना के पास से एक एंड्रॉयड फोन जब्त किया है। डीआईजी (साउथ) की रिपोर्ट पर संबंधित असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है और बैंगलोर सेंट्रल जेल के एसपी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इस घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।

अमेरिकी वीज़ा के लिए फर्जीवाड़ा : आंध्र प्रदेश का युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी दूतावास की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आंध्र प्रदेश के 25 वर्षीय युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। युवक पर गैर-आप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करते समय फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप है। घटना 7 अगस्त को नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में हुई, जहाँ युवक वीजा इंटरव्यू के लिए पहुंचा था। आरोपी ने अपनी शैक्षिक योग्यता के रूप में राजस्थान के एक विश्वविद्यालय से कंप्यूटर्स में बैचलर ऑफ कॉमर्स की फर्जी डिग्री पेश की। इतना ही नहीं आरोपी ने 35,000 रुपये मासिक वेतन दिखाने वाला एक कंपनी का अप्रैजल पत्र और द्वाइ साल के अनुभव का दावा करने वाला अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया। वित्तीय स्थिति को मजबूत दिखाने के लिए, युवक ने 1.2 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्शाने वाला नेटवर्थ प्रमाण पत्र और बैंक खातों में 45 व 50 लाख रुपये का बैलेंस दिखाया। हालाँकि, इंटरव्यू के दौरान छूछाछ में युवक टूट गया और स्वीकार किया कि कभी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं की और सभी शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी थे। युवक ने बताया कि ये फर्जी दस्तावेज विजयवाड़ा के वीजा एजेंट नितिन ने उपलब्ध कराए थे। युवक ने माना कि मैंने केवल दो-द्वाइ महीने ही काम किया था और रोजगार संबंधी दस्तावेज उसके चाचा की कंपनी ने दिए थे।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद : सपा सांसद का भाजपा पर बड़ा हमला, श्रद्धालु घटने का दावा

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर तीखा हमला कर दावा किया है कि इस प्रकरण में कुछ छोटे लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी मछली को बचाया गया है। उन्होंने मोदी सरकार से इस पूरे मामले पर सदन में जवाब देने की मांग की है।

सांसद प्रसाद ने अयोध्या की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंचते थे और बड़ी संख्या में सोने, चांदी व नकदी का चढ़ावा चढ़ाया जाता था। उनके अनुसार, अब श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है और रोजाना 10 हजार तक की भीड़ भी नहीं पहुंच रही है। सांसद प्रसाद ने दावा किया कि पहले जहां लाखों रुपये का चढ़ावा आता था, वहीं अब 5, 11, 21 और 51 रुपये लगी छोट्टी रकम ही चढ़ावे में आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अयोध्या की मर्यादा को तोड़ने और कलंकित करने का काम किया है। उन्होंने चंदा चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच और इसके पीछे के दोषियों को सामने लाने की मांग भी की। वहीं, राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद के लिए साक्षात्कार जारी हैं। उम्मीदवारों से इंटरव्यू से पहले करीब तीन दर्जन सवालों वाला ऑनलाइन गृगल फॉर्म भरवाया गया। इन सवालों में प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े प्रश्न शामिल थे। उम्मीदवारों से पूछा गया कि क्या वे शिक्षा रखते हैं, जनरल पनहते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी, और क्या वे शराब का सेवन करते हैं। हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था को लेकर भी सवाल किए। साक्षात्कार में प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व कौशल, धार्मिक-सामाजिक जुड़ाव और मंदिर के भविष्य को लेकर उनके दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया गया है। मंगलवार को 18 में से 8 उम्मीदवारों का आमने-सामने साक्षात्कार हुआ, जिसमें चार पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल थे।

पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का किया विमोचन

-कार्यक्रम में शॉर्टकट के दौर में युवाओं को सावधान रहने का दिया संदेश

नई दिल्ली(एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रामनाथ कोविंद की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में एक मिसाल कायम की है। पद छोड़ने के बाद भी रामनाथ कोविंद देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वह ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष भी हैं। पीएम मोदी ने कोविंद की आत्मकथा ‘भारतीय गणतंत्र की विजय- मेरा जीवन, मेरा संघर्ष’ का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि देश की नई पीढ़ी को इस किताब को पढ़ना चाहिए और कोविंद के अनुभवों से सीखना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि किताब का शीर्षक बिल्कुल सही है। इसमें रामनाथ कोविंद के व्यक्तिगत जीवन और संघर्षों की कहानी है, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ उनकी



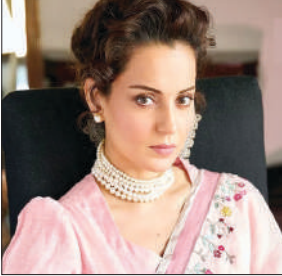
व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि भारतीय गणतंत्र और लोकतंत्र की जीत है। पीएम ने कार्यक्रम में एक वाक्ये का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जाते थे। तब प्रोटोकॉल के बावजूद रामनाथ कोविंद अक्सर औपचारिकताओं से हटकर उनसे बातचीत करते थे। इतना ही नहीं, वह प्रधानमंत्री को विदा करने के लिए खुद कार के

दरवाजे तक आते थे। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कई बार पूर्व राष्ट्रपति से ऐसा न करने को कहा, लेकिन उन्होंने अपनी यह विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद के गांव परीछ रामनाथ कोविंद से मिलने जाते थे। पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद के गांव परीछ रामनाथ कोविंद से मिलने जाते थे। पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद के गांव परीछ रामनाथ कोविंद से मिलने जाते थे।

पीएम मोदी ने कहा कि कोविंद का यह भावुक अंदाज पूरे देश ने देखा उनके व्यवहार ने दुनिया के सामने भारत के संस्कार और सांस्कृतिक मूल्यों की ऐसी तस्वीर पेश की, जिस पर हर भारतीय को गर्व होता है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जेन-जी को भी खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज के सोशल मीडिया के जमाने में कई इम्प्लुएंसर्स युवाओं को आकर्षित करते हैं, लेकिन इस शॉर्टकट के दौर में भी युवाओं को सावधान रहना चाहिए। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन पर लिखी एक लाइन का उदाहरण देते हुए कहा रेलवे स्टेशन पर भी लोग ब्रिज से जाने की बजाय पटरी पार करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि यह गलत शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि अगर वे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी पसंद के लोगों की ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए।

गटर जनरेशन कहकर फंसी कंगना! 21 को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी विवादित बयानों के चलते एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में धिरती नजर आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों और जेन जेड के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उत्तर प्रदेश के आगरा की एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। यह याचिका जंतर-मंतर पर प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों, उनके माता-पिता और युवाओं पर की गई टिप्पणियों के संबंध में दाखिल की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है, जिस दिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।



जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तब अभिनेत्री ने उन्हें गटर जनरेशन या गटर छाप कर दिया और उनके माता-पिता के खिलाफ भी अपमानजनक बातें कहीं। वकील ने इसे देश के युवाओं और छात्रों का सीधा अपमान बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है, जिस दिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। याचिकाकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि स्थानीय अदालत से इस मामले में राहत नहीं मिलती है, तो वह इस कानूनी लड़ाई को उच्च न्यायालय और जरूरत पड़ने पर देश के उच्चतम न्यायालय तक लेकर जाएंगे।

मुंबई के कुर्ला और घाटकोपर में जमीन धंसने से अब तक 6 की मौत

कई लोगों के दबे होने की आशंका

मुंबई (एजेंसी)। मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई है। बुधवार तड़के भारी बारिश के कारण शहर के अलग-अलग इलाकों में भूस्खलन और घरों के ढहने की दुःखद घटनाएं सामने आई हैं। कुर्ला के चिराग नगर और घाटकोपर के अशोकनगर इलाके में पहाड़ का हिस्सा गिरने और चॉल ढहने की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई है, वहीं मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसा बुधवार सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक हुए भूस्खलन के कारण गौसिया चॉल समेत अन्य मकान मलबे में तब्दील हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, अग्निशमन दल, पुलिस, एंबुलेंस और राहत एवं बचाव टीमों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मलबे को हटाने के लिए मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और घायलों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच चुके हैं ताकि राहत कार्यों की निगरानी की जा सके और पीड़ितों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। हर साल मानसून के दौरान मुंबई में इस तरह के हादसे चिंता का विषय बनते हैं। पहाड़ों के ढलान और असुरक्षित इलाकों में बनी चॉल व अस्थायी मकान बारिश में सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। प्रशासन और बचाव एजेंसियां समय-समय पर लोगों को ऐसे क्षेत्रों को खाली करने की चेतावनी देती रही हैं और सतर्क रहने की अपील करती हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग इन असुरक्षित घरों में रहने को मजबूर हैं। ये निर्माण न केवल भौगोलिक रूप से जोखिम भरे क्षेत्रों में होते हैं, बल्कि बारिश का दबाव डेल्टे में भी है। ऐसे जानलेवा घटनाएं होती हैं। इस बीच, मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों-जैसे ठाणे,



पालघर और रायगढ़-के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शहर में मानसून की बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने पहले ही जलभराव की समस्याएं पैदा कर दी हैं, और अब इन भूस्खलनों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। फिलहाल पूरा ध्यान मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने पर केंद्रित है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों और जंजर मकानों के पास जाने से बचें और अत्यधिक सतर्कता बरतें।

पालघर और रायगढ़-के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शहर में मानसून की बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने पहले ही जलभराव की समस्याएं पैदा कर दी हैं, और अब इन भूस्खलनों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। फिलहाल पूरा ध्यान मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने पर केंद्रित है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों और जंजर मकानों के पास जाने से बचें और अत्यधिक सतर्कता बरतें।

लाल किले पर 80 साल बाद सुनाई देगा वंदे मातरम: क्यों बदला इतिहास और क्या है नया कानून

नई दिल्ली (एजेंसी)। इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नया इतिहास रचा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले, पूरे लाल किले में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गुंज सुनाई देगी। आजादी के बाद पहला मौका है, जब स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक और मुख्य प्रोटोकॉल में वंदे मातरम को इतना विशिष्ट स्थान मिला है। अब तक, कड़े सैन्य और राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत ध्वजारोहण समारोह में केवल राष्ट्रगान जन गण मन को प्रार्थमिकता मिलती थी। लेकिन रक्षा मंत्रालय के नए और ऐतिहासिक प्रोटोकॉल बदलावों के तहत, इस बार पूरे वंदे मातरम के

ओजस्वी स्वरों से देश के स्वाभिमान का एक नया अध्याय शुरू होगा। इस बदलाव की जड़ें लंबे समय से चली आ रही बहस में निहित हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस कविता के शुरुआती दो पद मातृभूमि की सामान्य स्तुति करते हैं, लेकिन बाद के पदों में हिंदू देवियों, विशेषकर दुर्गा, का स्पष्ट उल्लेख और उनसे जुड़ी कल्पनाएं हैं। इन्हीं धार्मिक संदर्भों पर मुस्लिम लोग और अन्य समूहों की आपत्तियां थीं, इसलिए 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर जैसी हस्तियों की सलाह पर बाद के पदों को हटाने और सार्वजनिक राजनीतिक मंचों के लिए

केवल शुरुआती दो पदों का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। भारत के गणतंत्र बनने पर, 1950 में संविधान सभा ने जन गण मन को आधिकारिक राष्ट्रगान और वंदे मातरम के शुरुआती दो पदों को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। इस प्रकार उन्हें समान सम्मान दिया गया, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल के लिए धर्मनिरपेक्ष संतुलन भी बनाए रखा गया। अब संसद ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026 पारित किया है, इसके तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर कानूनी दर्जा मिला है। यह नया कानून, जो पिछले महीने जुलाई में ही पास किया गया,

जान-बूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालने या इसका अनादर करने को दंडनीय अपराध बनाता है। यह संशोधन 1971 के उस अधिनियम में किया गया है जो पहले केवल राष्ट्रगान से संबंधित था। इस ऐतिहासिक बदलाव के तहत, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में, राष्ट्रगान से ठीक पहले लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम बजाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा ध्वज भी लेकर उड़ेगा, जो इस अयोजन की भव्यता को और बढ़ाएगा।

दो किसानों को ले गए थे बांग्लादेशी-पलैग मीटिंग के बाद हुई रिहाई

नई दिल्ली। (एजेंसी)। भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उस समय अचानक तनाव गहरा गया जब बांग्लादेशी ग्रामीणों ने सीमा पार कर दो भारतीय किसानों का अपहरण कर लिया। यह घटना पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के सीमावर्ती इलाके में घटी, जहां खेत में काम कर रहे दो भारतीय किसानों को जबरन खींचकर बांग्लादेश ले जाया गया। हालांकि, दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच तत्काल हुई उच्चस्तरीय पलैग मीटिंग के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और आपसी सहमति से सभी नागरिकों को सुरक्षित रिहा करा लिया गया। विवाद की पूरी शुरुआत मंगलवार सुबह बांग्लादेश के मेहेरपुर स्थित इच्छाखाली बॉर्डर के पास हुई। स्थानीय रिपोटों के अनुसार, अब्दुल मन्जान नामक एक बांग्लादेशी किसान सीमावर्ती क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर फसल पर कीटनाशक छिड़क रहा था, जिसके चलते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने उसे हिरासत में ले लिया था। इस कार्रवाई से आक्रोशित होकर दर्जनों बांग्लादेशी ग्रामीण भड़क उठे और सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने खेतों में काम कर रहे सचिन कर्मकार और नारायण देव नामक दो भारतीय किसानों को बंधक बना लिया और उन्हें बॉर्डर गई बांग्लादेश (बीजीबी) के हवाले कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी गई और तनाव को कम करने के लिए मंगलवार दोपहर इच्छाखाली सीमा पर ज़ीरो लाइन पर दोनों देशों के बलों के बीच पलैग मीटिंग बुलाई गई। लंबी बातचीत के बाद सहमति बनी, जिसके तहत बीएसएफ ने हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी नागरिक को बीजीबी को सौंप दिया, और इसके बदले में बांग्लादेशी ग्रामीणों द्वारा उठाए गए दोनों भारतीय किसानों को सुरक्षित वापस भारत के हवाले कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि सीमा पार से भारतीय नागरिकों के अपहरण की इस क्षेत्र में हाल के दिनों में यह दूसरी बड़ी घटना है।

राहुल गांधी बोले- लेकर नहीं सुनना, पैलेट गन का आदेश दिया तो शाह इस्तीफा दें

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में चर्चा के आह्वान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई लेकर नहीं सुनना है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लोकसभा में विश्वश के नेता राहुल गांधी ने कहा, कि देश की युवा पीढ़ी अमित शाह के काल्पनिक भाषण सुनने में दिलचस्पी नहीं रखती। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश आखिर किसने दिया था। राहुल गांधी ने सवाल किया कि किसके आदेश पर एक छात्र को कथित तौर पर अंधा कर दिया गया और दूसरे छात्र को गोली मारी गई। उन्होंने यह भी पूछा कि छात्रों को कीलों वाली लाठियों से पीटने का आदेश किसने दिया था।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें और युवाओं को गृह मंत्री की सफाई या तर्क नहीं चाहिए।

उनकी मांग है कि सरकार पहले यह स्पष्ट करे कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग का आदेश किस स्तर से दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब तक इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तब तक किसी तरह का लेकर या सामान्य चर्चा स्वीकार नहीं की जाएगी। राहुल गांधी ने इस धुंड़े पर सरकार को घेरते हुए कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि पैलेट गन चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।



स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, रातभर चलाई जा रही सघन चेकिंग

नई दिल्ली (एजेंसी)। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा है। सुरक्षा में कोई वृक न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में देर रात मेगा सुरक्षा अभियान चलाया। रात 11 बजे से 2 बजे तक दिल्ली के तमाम जिलों में गस्त के साथ सघन चेकिंग की गई। द्वारका मोंड पर पुलिसकर्मियों ने पूरी सतर्कता के साथ आधी रात को पैट्रोलिंग की। अधिकारियों ने गाड़ियों की सघन जांच की और हर गुजरने वाली कार की अंदर-बाहर से अच्छी तरह तलाशी ली गई। सिर्फ सुरक्षा जांच में पास होने वाली गाड़ियों को ही आगे जाने की इजाजत दी गई।

इसी तरह उत्तम नगर में पुलिस टीमों ने आधी रात को सघन चेकिंग अभियान चलाया। हवाके की मुख्य सड़कों से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोका गया और उसकी बारीकी से जांच की गई। इस निगरानी का मकसद पूरे शहर में पूरी सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है। सीलमपुर इलाके में भी दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान, सदिध वाहनों और लोगों पर नजर रखी गई। सुरक्षा अभियान के तहत पुलिसकर्मियों को स्थानों पर तैनात किया गया। वहीं, पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पीकेट लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की जांच की। इस दौरान सदिध वाहनों और लोगों पर विशेष नजर रखी गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और किसी भी सदिध गतिविधि को रोकने के लिए इस तरह के अभियान जारी रहेंगे।

फैल रहा वायब्रियो वल्निफिकस बैक्टीरिया, पाया जाता है समुद्री और खारे पानी में

-विशेषज्ञों ने दी चेतावनी- बैक्टीरिया गंभीर घाव का कारण बनकर हो सकता है जानलेवा

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका के कुछ तटीय इलाकों में इन दिनों समुद्र किनारे जाने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। यहां वायब्रियो वल्निफिकस नामक एक खतरनाक बैक्टीरिया, जो गर्म समुद्री और खारे पानी में पाया जाता है। हाल के महीनों में इसके संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमेरिका के लुइसियाना राज्य में इस साल अब तक नौ लोग इसकी चपेट में आए हैं, जिनमें सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पांच लोगों की मौत हो चुकी है। गंभीर मामलों में यह बैक्टीरिया शरीर के ऊतकों को तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे आम बोलचाल में प्लेश-ईटिंग बैक्टीरिया यानी मांस को नुकसान पहुंचाने वाल बैक्टीरिया कहा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक वायब्रियो वल्निफिकस प्राकृतिक रूप से गर्म समुद्री और खारे-मीठे पानी के मिश्रित क्षेत्रों में पाया जाता है। संक्रमण मुख्य रूप से दो तरीकों से फैलता है। पहला यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर कट, घाव या त्वचा पर



चोट हो और वह दूषित समुद्री पानी के संपर्क में आए। दूसरा- कच्चे या अधकचे समुद्री भोजन, विशेषकर ऑयस्टर जैसी शेलफिश के सेवन से। ज्यादातर संक्रमण सामान्य हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह बैक्टीरिया रक्त संक्रमण और गंभीर घाव का कारण बनकर जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्री पानी के संपर्क के बाद यदि घाव के आसपास लालिमा, सूजन, तेज दर्द, त्वचा का रंग बदलना, बुखार, ठंड लगना या त्वचा पर छाले बनने जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टरों की मदद लें। गंभीर स्थिति में ऊतक काले पड़ने लगते हैं और संक्रमण तेजी से फैल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि देश की लंबी समुद्री तटरेखा और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सतर्क रहने की जरूरत है। मछुआरे, समुद्री खाद्य पदार्थों से जुड़े

कर्मचारी और नियमित रूप से समुद्र में जाने वाले लोग इस बैक्टीरिया के संपर्क में आने की आशंका वाले समूहों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल भारत में अमेरिका जैसी व्यापक स्थिति या किसी बड़े प्रकोप की पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। यदि शरीर पर कोई खुला घाव हो तो समुद्र या खारे पानी में जाने से बचें। यदि घाव समुद्री पानी के संपर्क में आ जाए तो उसे तुरंत साबुन और स्वच्छ पानी से अच्छे तरह धोएं। साथ ही समुद्री भोजन, विशेष रूप से शेलफिश, को हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। विशेषज्ञों के मुताबिक गर्म मौसम में यह बैक्टीरिया ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए बारिश और गर्मी में तटीय क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना ही सबसे प्रभावी बचाव है।



राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा, अधिकाधिक मामलों के निष्पादन पर जोर

चेक बाउंस समेत समझौता योग्य मामलों के त्वरित निपटारे का निर्देश

बिभा संवाददाता

साहेबगंज। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निदेशानुसार आगामी 12 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों एवं अधिकाधिक मामलों के निष्पादन को लेकर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहेबगंज अखिल कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों को अधिक से अधिक समझौता योग्य मामलों



को चिन्हित कर त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निष्पादन की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लंबित मामलों की पहचान, पक्षकारों से समय पर संपर्क, आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने तथा समझौते की संभावनाओं वाले मामलों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया

गया। साथ ही बैठक में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) के चेक अनादरण (चेक बाउंस) मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष चर्चा की गई। संबंधित न्यायालयों को आवश्यक अभिलेख समय पर उपलब्ध कराने तथा पक्षकारों से संपर्क स्थापित कर समझौते की संभावना वाले मामलों

को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्रिय सहयोग करने का निर्देश दिया गया। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में धन वसूली, बैंक ऋण, एनआई एक्ट, बिजली एवं पानी के बिल, भरण-पोषण, श्रम विवाद, आपराधिक शमनीय अपराध, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता एवं बीमा विवाद सहित विभिन्न समझौता योग्य मामलों का निपटारा आपसी सहमति एवं सुलह के आधार पर किया जाएगा। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज द्वारा लंबित समझौता योग्य मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही, आम लोगों को राष्ट्रीय

लोक अदालत के लाभों से अवगत कराने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने कहा कि लोक अदालत लंबित मामलों के निष्पादन के साथ-साथ आपसी सहमति, सुलह एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवादों के समाधान का प्रभावी मंच है। इसके माध्यम से पक्षकारों को समय एवं धन की बचत के साथ लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। साथ ही उन्होंने प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत को संबंधित न्यायालयों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर अधिकाधिक मामलों का त्वरित एवं सरल तरीके

से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले के नागरिकों एवं संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे 12 सितम्बर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। वहीं समझौता योग्य मामलों के निःशुल्क एवं त्वरित समाधान के इच्छुक पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय मुख्य भवन, प्रथम तल, साहेबगंज अथवा अनुमंडल विधिक सेवा समिति, राजमहल में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम नागरिकों से आपसी सहमति के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करारकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

सशक्त युवा, सशक्त भारत अभियान से युवाओं को किया जा रहा जागरूक



बिभा संवाददाता

साहेबगंज। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निदेशानुसार साहेबगंज जिले में हजाजित योजना, 2025ह्में के तहत ह्हाससक्त युवा, सशक्त भारतह्हा अभियान का व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं पूरे माह चलने वाले इस विशेष अभियान को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहेबगंज अखिल कुमार द्वारा विशेष प्रधानता दी गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष अखिल कुमार ने अभियान की महत्ता को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहेबगंज के सचिव विश्वनाथ भगत को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए अभियान का प्रभावी एवं व्यापक अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिले के अधिक से अधिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीण तथा सामुदायिक क्षेत्रों तक विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि युवा अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकें। निर्देश के अनुपालन में सचिव श्री विश्वनाथ भगत के द्वारा

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को उनके मौलिक अधिकारों, किशोर न्याय व्यवस्था, कानून के उल्लंघन की स्थिति में किशोरों के अधिकार, पहली बार अपराध करने वाले युवाओं के पुनर्वास एवं सुखधारा में वापसी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी प्राधानों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही वर्तमान समय की चुनौतियों को देखते हुए युवाओं को साइबर अपराध, एआई आधारित धोखाधड़ी, डीपफेक, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी एवं अन्य डिजिटल अपराधों से निवारण के व्यावहारिक उपायों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग विरोधी कानून एवं नालसा रैगिंग पर छात्र जागरूकता संसाधन 2026 के संबंध में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी जा रही है। अभियान का उद्देश्य केवल कानूनी जानकारी देना ही नहीं, बल्कि युवाओं को जिम्मेदार, जागरूक और सशक्त नागरिक बनाना है। उन्होंने बताया कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स न्याय मित्र इस अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएलवीएस की सक्रिय भागीदारी से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं एवं आम लोगों तक विधिक जागरूकता का संदेश पहुंचाया जा रहा है।

परियोजना निदेशक ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण, मरीजों से लिया फीडबैक



बिभा संवाददाता

साहेबगंज। उपायुक्त के निदेशानुसार परियोजना निदेशक संजय कुमार दास ने बुधवार को सदर अस्पताल साहेबगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, मरीजों को प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं तथा अस्पताल की समग्र व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना था। वहीं औचक निरीक्षण के दौरान परियोजना निदेशक ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी, आपातकालीन सेवाओं, दवा वितरण, जांच एवं अन्य प्रमुख चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता, साफ-सफाई, मरीजों की सुविधा, चिकित्सकीय सेवाओं की उपलब्धता तथा आवश्यक संसाधनों की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों से अस्पताल में आने वाले मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा मरीजों एवं उनके परिजनों से भी बातचीत कर चिकित्सा सुविधा, दवा, जांच एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में

फीडबैक लिया। वहीं परियोजना निदेशक ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को सम्मानजनक व्यवहार के साथ समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने तथा मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं आमजनों से सीधे जुड़ी हुई हैं और सरकारी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज, आवश्यक दवाएं एवं जांच की सुविधा सुचारु रूप से मिले, इसे लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की संभावनाओं को चिन्हित करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर बल दिया।

संक्षिप्त खबरें

अभिभावकों ने विद्यालय के बेहतर संचालन का लिया संकल्प, रंजू देवी को मिली अध्यक्ष की जिम्मेदारी

साहेबगंज (बिभा)। उत्कर्मित उच्च विद्यालय सोतीचौकी पांगड़ों में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन को लेकर बुधवार को आयोजित बैठक में अभिभावकों और ग्रामीणों ने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान शनिचर मुंडा ने की। वहीं समिति के पुनर्गठन के दौरान अभिभावकों ने सर्वसम्मति से रंजू देवी को अध्यक्ष और सुमन कुमारी को उपाध्यक्ष चुना। वहीं फिरदेस खतून को संयोजिका की जिम्मेदारी दी गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के चयन के बाद उपस्थित अभिभावकों एवं ग्रामीणों ने विद्यालय के विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी का भरोसा जताया। वहीं पर्यवेक्षक फैजल अफरोज की मौजूदगी में समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापिका सुस्मिता सोरेन, शिक्षक अण्णोजा सिंह आर्या, अजय कुमार ठाकुर, रमेश कुमार समेत अन्य शिक्षक, अभिभावक एवं ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष रंजू देवी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि समिति विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता देते हुए विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, अनुशासन और विकास से जुड़े कार्यों में अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करेंगी।



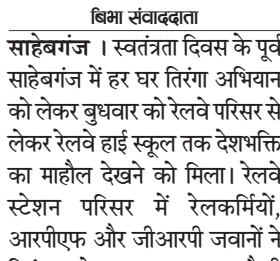
उधवा में जाति-आवास प्रमाण-पत्र के हजारों आवेदन लंबित, विधायक प्रतिनिधि ने सीओ से की मुलाकात

उधवा(बिभा)। उधवा अंचल कार्यालय में जाति और आवास प्रमाण-पत्र के लिए आवेदनों का अंबार लग गया है। आवेदनों की संख्या घटने के बजाय बैकलॉग लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी समस्या को लेकर राजमहल विधायक प्रतिनिधि मो. मारुफ उर्फ गुड्डू और कांग्रेस जिला महासचिव ऐनुल हक अंसारी ने सोमवार को अंचलाधिकारी उधवा आशीष कुमार मंडल से मुलाकात कर हजारों लंबित आवेदनों का मुद्दा उठाया। मुलाकात के दौरान नेताओं ने बताया कि उधवा प्रखंड में बड़ी आबादी के पास साक्षरता प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं के बीच भय का माहौल बना हुआ है। प्रखंड में हजारों निरक्षर मतदाताओं के लिए जाति और निवास प्रमाण-पत्र ही सबसे आसान और सहज दस्तावेज है। लेकिन अब भी हजारों आवेदकों के प्रमाण-पत्र लंबित पड़े हैं। जिससे लोगों में असमंजस और घबराहट है। वहीं अंचलाधिकारी आशीष कुमार मंडल ने दोनों नेताओं की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्चर्य किया कि एसआईआर प्रक्रिया में मांगे जाने वाले दस्तावेज के लिए जो भी आवेदक जाति अथवा आवास प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेंगे। उन्हें अपने आवेदन के साथ एसआईआर प्रपत्र की नोटिस सलन करनी होगी। सीओ ने कहा कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर जल्द से जल्द प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा। किसी भी पात्र व्यक्ति को प्रमाण-पत्र के अभाव में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बैठक के बाद विधायक प्रतिनिधि मो. मारुफ उर्फ गुड्डू और कांग्रेस जिला महासचिव ऐनुल हक अंसारी ने संयुक्त रूप से कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी मतदाता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास अन्य दस्तावेज नहीं हैं। वे तुरंत जाति-आवास प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करें और साथ में एसआईआर नोटिस लगा दें। उनका काम प्राथमिकता से होगा।

उधवा में कल 9 घंटे बाधित रहेगी बिजली,33 केवी विद्युत उपकेन्द्र से जुड़े कई क्षेत्र रहेंगे प्रभावित

उधवा (बिभा)। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गुरुवार को उधवा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। 33 के.वी. विद्युत शक्ति उपकेन्द्र उधवा से निर्गत 11 के.वी. इंग्लिश फीडर की जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने और आवश्यक रखरखाव का कार्य किया जाना है। इस मरम्मत के कारण सुबह 09:00 बजे से लेकर शाम 06:00 बजे तक बिजली आपूर्ति पूर्णतः बंद रहेगी। इस संदर्भ में विद्युत कनीय अभियंता चंदन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मेटेनैस कार्य से इंग्लिश,मनिहारी टोला गोलहबाड़ी,अमानत दियारा,पूर्वी उधवा,पश्चिमी उधवा,पलशगाछी,उत्तर पियारपुर तथा दक्षिण पियारपुर सहित आसपास के बड़े इलाके प्रभावित रहेंगे। कनीय विद्युत अभियंता ने क्षेत्र के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि जर्जर तारों को बदलने से भविष्य में निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। कार्य पूर्ण होते ही विद्युत आपूर्ति तत्काल बहाल कर दी जाएगी। प्रशासन ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे बिजली से जुड़े अपने जरूरी काम सुबह 9:00 बजे से पहले ही निपटा लें।

तिरंगे के रंग में रंगा साहेबगंज, रेलवे परिसर से स्कूल तक गूंजा देशभक्ति का संदेश



बिभा संवाददाता

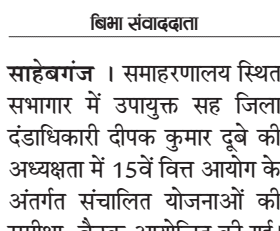
साहेबगंज। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व साहेबगंज में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बुधवार को रेलवे परिसर से लेकर रेलवे हाई स्कूल तक देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। रेलवे स्टेशन परिसर में रेलकर्मियों, आरपीएफ और जीआरपी जवानों ने तिरंगा लेकर जागरूकता रैली निकाली, वहीं पूर्व रेलवे उच्च विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति का संदेश दिया। वहीं स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व स्टेशन मास्टर गुड्डू कुमार ने किया। रैली स्टेशन परिसर से निकलकर स्टेशन चौक, ग्रीन होटल मोड़ समेत प्रमुख चौक-चौराहों से होते हुए पुनः स्टेशन परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान हाथों में तिरंगा



लिए रेलकर्मियों और सुरक्षा जवानों ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। स्टेशन मास्टर गुड्डू कुमार ने कहा कि ह्हाहर घर तिरंगाह्हा अभियान का उद्देश्य लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाना है। उन्होंने रेलकर्मियों के साथ आम लोगों से भी अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। कार्यक्रम में एएसई

जागरूकता तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर विद्यार्थी विद्यालय से निकले और शहर के प्रमुख चौक-चौराहों से गुजरते हुए लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा के दौरान विद्यार्थियों ने आम लोगों को भी अभियान से जुड़ने और अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय पहुंचने के बाद अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाओं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। दोनों आयोजनों के माध्यम से साहिबगंज में स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति का संदेश पुनः-पुनः उच्च विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने बुधवार को

15वें वित्त आयोग की योजनाओं की डीसी ने की समीक्षा, गुणवत्तापूर्ण कार्य और तेजी से राशि खर्च करने का निर्देश



बिभा संवाददाता

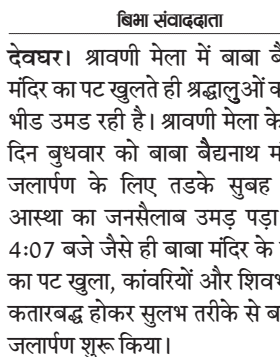
साहेबगंज। समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक के दौरान जिला परिषद, प्रखंडवार पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के विरुद्ध किए जा रहे व्यय एवं योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा राशि के व्यय की प्रगति में तेजी



लाने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने आगामी जी.पी.डी.पी के तहत चर्चयित योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता देने तथा योजनाओं से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियां एवं निर्धारित मानकों को समय पर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने

श्रावणी मेला में वर्चुअल रियलिटी शिविर बना श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र देवघर। श्रावणी मेला में बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ उनके आध्यात्मिक अनुभव को समृद्ध करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आधुनिक तकनीक और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मेला क्षेत्र में लगाए गए विशेष वर्चुअल रियलिटी (वीआर) शिविर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।इन वीआर शिविरों के माध्यम से श्रद्धालुओं को 3-डी एनीमेशन और अत्याधुनिक ग्राफिक्स तकनीक के जरिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास, द्वाश्र्श ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी पौराणिक कथा और देवघर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सफर की जानकारी दी जा रही है।

श्रावणी मेला में पट खुलते ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ रहे श्रद्धालु



बिभा संवाददाता

देवघर। श्रावणी मेला में बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रावणी मेला के 14वें दिन बुधवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण के लिए तड़के सुबह से ही आस्था का जनसेलाब उमड़ पड़ा। प्रातः 4:07 बजे जैसे ही बाबा मंदिर के गर्भगृह का पट खुला, कांवरियों और शिवभक्तों ने कतारबद्ध होकर सुलभ तरीके से बाबा पर जलार्पण शुरू किया। पट खुलते ही पूरा मेला क्षेत्र और रूट लाइन बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान हो उठी। सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर बाबा धाम पहुंचे हजारों कांवरिया पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ बाबा का जयघोष करते हुए मंदिर की ओर बढ़ते रहे। श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन की ओर से की गई चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच कांवरिया अनुशासित तरीके से कतार में आगे बढ़ रहे हैं। अहले सुबह से ही बीएड कॉलेज से कांवरियों की लंबी कतार लगी रही, जो निर्धारित रूट लाइन के माध्यम से बाबा मंदिर की ओर बढ़ती

श्रावणी मेला में खामियां दिखे तो व्यूआर कोड स्कैन कर करें शिकायत देवघर। राजकीय श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए तकनीक का सहारा लिया है। मेला क्षेत्र में जगह-जगह व्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर श्रद्धालु किसी भी प्रकार की असुविधा या कमी की शिकायत सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने कहा कि राज्य सरकार के निदेशानुसार श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं की नगरी से सुखद एवं बेहतर अनुभव लेकर अपने गंतय तक भेजना है? उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में यदि किसी श्रद्धालु को साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, होस्टिंग प्वाइंट, प्रशासनिक शिविर, स्वास्थ्य शिविर या कांवरिया रूटलाइन से संबंधित कोई समस्या दिखाई देती है, तो वे संबंधित स्थान पर लगे व्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। व्यूआर कोड स्कैन करते ही गुगल फर्म खुलेगा, जहां शिकायत दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। श्रद्धालु अपनी समस्या लिखने के साथ जरूरत पड़ने पर उसकी तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं। इससे प्रशासन को समस्या की वास्तविक स्थिति और स्थान की जानकारी मिलने में आसानी होगी। प्राप्त शिकायतों की निगरानी के लिए मेला कंट्रोल रूम में एक विशेष सेल बनाया गया है। श्रद्धालु की ओर से दर्ज की गई शिकायत और अपलोड की गई तस्वीर कंट्रोल रूम के सिस्टम में प्राप्त होते ही संबंधित विभाग को टैग कर समस्या के समाधान का निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद मेला में प्रतिनिधित्व संबंधित टीम मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान करेगी। प्रशासन ने शिकायत प्रणाली को इस तरह विकसित किया है कि शिकायत मिलने से लेकर उसके समाधान तक पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि है। उन्होंने अपील की कि यदि मेला क्षेत्र में कहीं भी कोई कमी, असुविधा या सुधार की आवश्यकता दिखाई दे, तो श्रद्धालु तत्काल वहां उपलब्ध व्यूआर कोड स्कैन कर प्रशासन को जानकारी दें, ताकि समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

रही। रूट लाइन में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के साथ पेयजल, स्वास्थ्य और स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जगह-जगह तैनात पुलिसकर्मी एवं प्रशासनिक अधिकारी कांवरियों की सुविधा और व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि दोपहर बाद अचानक हुई बारिश से मौसम में थोड़ी शीतलता आई तो कांवरियों में फिर उत्साह नजर आया और कांवरिया पथ पर उनकी रफार बढ़ गई। लंबी दूरी तय कर बाबा धाम पहुंच रहे कांवरिया थकान दूर करने के लिए विभिन्न कांवरिया सेवा शिविरों का भी सहारा ले रहे हैं। यही वजह है कि दिन के समय शहर के अंदर कांवरियों की मौजूदगी अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है, लेकिन शाम होते-होते कांवरिया पथ से लेकर शहर के प्रमुख मार्ग एक बार फिर बोल बम के जयघोष से गुलजार हो उठते हैं।

रही। रूट लाइन में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के साथ पेयजल, स्वास्थ्य और स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जगह-जगह तैनात पुलिसकर्मी एवं प्रशासनिक अधिकारी कांवरियों की सुविधा और व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि दोपहर बाद अचानक हुई बारिश से मौसम में थोड़ी शीतलता आई तो कांवरियों में फिर उत्साह नजर आया और कांवरिया पथ पर उनकी रफार बढ़ गई। लंबी दूरी तय कर बाबा धाम पहुंच रहे कांवरिया थकान दूर करने के लिए विभिन्न कांवरिया सेवा शिविरों का भी सहारा ले रहे हैं। यही वजह है कि दिन के समय शहर के अंदर कांवरियों की मौजूदगी अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है, लेकिन शाम होते-होते कांवरिया पथ से लेकर शहर के प्रमुख मार्ग एक बार फिर बोल बम के जयघोष से गुलजार हो उठते हैं।

पूर्व रेलवे
निविदा सं.: ईएल-एमएलडीटी-ई-निविदा-453, दिनांक 10.08.2026, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (सा.), पूर्व रेलवे, मालदा टाउन, ऑफिस बिल्डिंग, पी.ओ.-ब्रल्लुलिया, जिला-मालदा, पिन-732102 (पश्चिम बंगाल) द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए अनुभवी एवं वित्तीय संपन्न ख्यातिप्राप्त फर्मों/एजेंसियों/ठेकेदारों से खुली ई-निविदा सूचना आमंत्रित की जाती है:
निविदा सं.: ईएल-एमएलडीटी-ई-निविदा-453, **कार्य का नाम :** 3 वर्ष की अवधि के लिए डिवीजनल रेलवे हॉस्पिटल, मालदा के ओटी में 2x7.5 टन फैकेन्ड एसी प्लांट और डीआरएम बिल्डिंग, मालदा के कंट्रोल रूम में स्थापित 5x11 टन क्षमता के स्कॉल कंटेनर युक्त एयर कूल्ड प्लेनो माउंटेड फैकेन्ड यूनिट एयर कंडीशनर का दैनिक संचालन और ओवरहॉल्स सहित व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी)। **निविदा मूल्य :** ₹. 29,82,415.65, **बयाना राशि :** ₹. 59,700/-, **निविदा कागजात का मूल्य :** शून्य। **ई-निविदा जमा करने की तिथि और समय :** दिनांक 18.08.2026 से 01.09.2026 को 15.30 बजे तक। **वेबसाइट का विवरण एवं सूचना पट :** वेबसाइट www.ireps.gov.in सूचना पट: **वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/ (सा.), पूर्व रेलवे, मालदा टाउन का कार्यालय।** निविदाकारों से अनुबंध है कि वेबसाइट www.ireps.gov.in में विस्तृत निविदा सूचना एवं कागजात देखें। किसी भी परिस्थिति में किसी मैनुअल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
MLD-161/2026-27
निविदा सूचना वेबसाइट www.ee.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है
हमें यहाँ देखें : **@EasternRailway**
 @easternrailwayheadquarter

युलु ने सीरीज सी फडिंग में जुटाए 9.3 करोड़

अगले दो साल में बेड़ा 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा मुंबई ।

इलेक्ट्रिक परिवहन मंच युलु ने अपने सीरीज सी वित्त पोषण दौर में 9.3 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक जुटा लिए हैं। इस पूंजी के साथ कंपनी ने अगले दो वर्षों में अपने इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े को चार गुना बढ़ाकर 2 लाख करने, सेवा नेटवर्क के विस्तार और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की अपनी योजनाओं को तेज करने का लक्ष्य रखा है। युलु के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने बताया कि यह वित्तपोषण कंपनी के कारोबारी मॉडल की मजबूती और मांग की व्यापक संभावनाओं की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि युलु भारत की शहरी स्थानीय परिवहन गतिविधियों की आधारशिला के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बजाज ऑटो और मैग्ना इंटरनेशनल इंक जैसी रणनीतिक साझेदारियों ने युलु को विशेष हार्डवेयर, प्रौद्योगिकी और व्यापक ऊर्जा बुनियादी ढांचे वाला एक एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन परिवेश बनाने में मदद की है। अब कंपनी युलु एक्सप्रेस के साथ शहरी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी प्रवेश करने की योजना बना रही है। यह ई-कॉमर्स, बाइक टैक्सी और त्वरित पार्सल डिलीवरी के लिए डिज़ाइन किया गया एक उच्च क्षमता वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। कंपनी का उद्देश्य इन विस्तार योजनाओं के माध्यम से टिकाऊ शहरी गतिशीलता में अपनी स्थिति मजबूत करना है।

आरडी इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 39 प्रतिशत बढ़त के साथ सूचीबद्ध नई दिल्ली ।

आरडी इंडस्ट्रीज का शेयर बुधवार को शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत के साथ सूचीबद्ध हुआ। कंपनी के शेयर ने अपने 53 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले करीब 39 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की, जिससे निवेशकों को लिस्टिंग के दिन ही उल्लेखनीय मुनाफा हुआ। कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को निवेशकों से भारी प्रतिक्रिया मिली थी। बीएसई पर आरडी इंडस्ट्रीज का शेयर 73.60 रुपये पर कारोबार शुरू किया, जो इसके निर्गम मूल्य से 38.86 प्रतिशत अधिक है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर यह 35.84 प्रतिशत की बढ़त के साथ 72 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। इस दमदार प्रदर्शन के साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2,119.10 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। कंपनी के 426 करोड़ रुपये के आईपीओ को निवेशकों ने हाथों-हाथ लिया था और पिछले सप्ताह श्रृंखार को बोली के अंतिम दिन यह 133.66 गुना से अधिक अभिदान के साथ बंद हुआ था। 50-53 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे वाले इस आईपीओ ने बाजार की स्वीकार्यता को दर्शाया है। आरडी इंडस्ट्रीज ऊर्जा भंडारण उत्पादों और गैर-लौह धातु कबाड़ के पुनर्चक्रण तथा अपशिष्ट से महत्वपूर्ण संसाधनों को पुनः प्राप्त करने का काम करती है।

ओला इलेक्ट्रिक को 7,240 करोड़ का पीएलआई लाभ

मंत्रालय ने बढ़ाई सेल उत्पादन प्रोत्साहन समयसीमा नई दिल्ली ।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) से बड़ी राहत मिली है। मंत्रालय ने कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी ओला सेल टेक्नोलॉजीज (ओसीटी) के लिए उन्नत रसायन सेल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की समयसीमा में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से ओला इलेक्ट्रिक को अपने 20 गीगावाट आवंटन के लिए 2031 तक पूरे पांच साल की पीएलआई अवधि मिलेगी, जिससे उसे कुल 7,240 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन लाभ प्राप्त हो सकेगा। कंपनी ने बुधवार को बताया कि यह प्रोत्साहन राशि अगली तिमाही से तिमाही आधार पर मिलनी शुरू हो जाएगी। ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक भविष अग्रवाल ने कहा कि संशोधित समयसीमा महज विस्तार से कहीं अधिक है; यह उनके सेल कारोबार की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल देती है। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक के पास 2.5 गीगावाट की स्थापित सेल विनिर्माण क्षमता है, जिसमें 3.5 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जा रही है। कंपनी ने कहा कि चालू तिमाही के अंत तक उसकी क्षमता 6 गीगावाट हो जाएगी, जो दिसंबर 2026 की संशोधित समयसीमा से काफी पहले शुरुआती स्थापित क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लेगी। लिथियम सेल इलेक्ट्रिक परिवहन, ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अंबानी 25.8 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर

बिड़ला परिवार से तीन गुना ज़्यादा संपत्ति, टॉप 300 व्यवसायों की कुल वैल्यू 138 लाख करोड़ रुपए

नई दिल्ली

बार्कलेज और हुरुन इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर परिवारों की सूची में अंबानी परिवार शीर्ष पर है। उनकी कुल संपत्ति 25.8 लाख करोड़ रुपये है, जो दूसरे स्थान पर मौजूद कुमार मंगलम बिड़ला परिवार की संपत्ति से लगभग तीन गुना अधिक है। यह रिपोर्ट देश में पारिवारिक व्यवसायों की बढ़ती आर्थिक शक्ति को रेखांकित करती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के 300 शीर्ष पारिवारिक व्यवसायों की कुल वैल्यू 138 लाख करोड़ रुपये थी। कुमार

मंगलम बिड़ला परिवार 8.1 लाख करोड़ रुपये और जिंदल परिवार 8 लाख करोड़ रुपये के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पिछले एक साल में इन तीनों परिवारों की संपत्ति 1.57 लाख करोड़ रुपए बढ़ी, जो मूल्यांकन 42 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा, जो देश के सूचीबद्ध बाजार पूंजीकरण का लगभग 9 फीसदी है। शीर्ष 10 में शामिल होने के लिए आवश्यक मूल्यांकन एक साल में 14 फीसदी बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस दौरान, वेदांत के अनिल अग्रवाल परिवार मूल्यांकन में 74.7 फीसदी वृद्धि के साथ तीन पायदान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर आ गया।

वहीं, एचसीएल टेक का नाडर और विप्रो का प्रेमजी परिवार रैंकिंग में नीचे खिसके, क्रमशः 38 और 2.3 फीसदी गिरावट के बाद अब आठवें और नौवें स्थान पर हैं। पहली पीढ़ी के सबसे धनी परिवारों में अग्रणी परिवार 19.57 लाख करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे है। उसके बाद भारती एयरटेल के सुनील भारती मित्तल (12.1 लाख करोड़) और सन फार्मा के दिलीप सांघवी (4.54 लाख करोड़) का परिवार है। इन 300 फैमिली समूहों ने पिछले दो सालों में औसतन हर दिन 4,076 करोड़ रुपये की संपदा जोड़ी है, और 54 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है।

बैंकों में 2.31 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के फॉंड, वसूली केवल 2.7 फीसदी

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों में खुलासा- 2021-26 के बीच 1 करोड़ से अधिक के 5,607 मामले

नई दिल्ली ।

वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में बड़े वित्तीय फ़ॉंड की चिंताजनक तस्वीर पेश की है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2026 के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 5,607 धोखाधड़ी मामलों में 2,31,710.12 करोड़ रुपए की

रकम शामिल थी, जिसमें से महज 6,283.14 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई। यह दर्शाता है कि 2,25,426.98 करोड़ रुपए की बड़ी राशि अभी भी फंसी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, जहां 2021 से 2024 तक बड़े फंड के मामलों और राशि में गिरावट देखी गई, वहीं वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में इनमें तेज उछाल आया।

वित्त वर्ष 24 में 641 मामलों के साथ 9,080.50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई, जो छह साल का निचला स्तर था। हालांकि, वित्त वर्ष 25 में यह संख्या बढ़कर 941 और वित्त वर्ष 26 में 1,330 हो गई, जो वित्त वर्ष 24 के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है। वित्त वर्ष 26 में धोखाधड़ी की राशि भी बढ़कर 46,559.84 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वर्ष से लगभग 55 फीसदी अधिक है। कुल मिलाकर, पांच सालों में 2.31 लाख करोड़ से अधिक के फंड में केवल 2.7 फीसदी (6,283.14 करोड़ रुपए) की ही वसूली हो सकी है। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम नुकसान नहीं है और कानूनी तथा रिकवरी प्रक्रियाओं के जरिए भविष्य में भी कुछ रकम वापस मिल सकती है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 188 अंक, निफ्टी 35 अंक गिरा

मुम्बई।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हवाी रहने से आई है। गत दिवस भी बाजार गिरावट पर बंद हुआ था। आज दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 187.90 अंक नीचे आकर 77,966.35 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 35.75 अंक फिसलकर 24,435.95

पर बंद हुआ। आज आईटी शेयरों में आई गिरावट का प्रभाव भी बाजार पर पड़ा है। कारोबार के दौरान सूचकांकों में निफ्टी आईटी में सबसे अधिक गिरावट रही। इसके बाद निफ्टी एफएमसीजी , निफ्टी कंजंशान , निफ्टी कंज्यूमर इयूरैबल्स 0.45 , निफ्टी हेल्थकेयर , निफ्टी ऑटो , निफ्टी सर्विसेज 0.14 और निफ्टी कर्मांडिटोज के शेयरों में भी गिरावट रही।

दूसरी ओर निफ्टी पीएसयू बैंक , निफ्टी मीडिया, निफ्टी इंडिया डिफेंस 0.70 , निफ्टी मेटल

रुपया बढ़त पर बंद



मुम्बई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया तीन पैसे की बढ़त के साथ ही 95.33 पर बंद हुआ। इससे पहले आज सुबह रुपया छह पैसे नीचे आकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.42 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की मुख्य वजह होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बनी अनिश्चितता है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.40 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में यह फिसलकर 95.42 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले छह पैसे की गिरावट दिखाता है। वहीं रुपया मंगलवार को छह पैसे टूटकर 95.36 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 फीसदी की बढ़त के साथ 99.87 पर रहा।

सेबी का प्रस्ताव: कमोडिटी डेरिवेटिव में एफपीआई की बढ़ेगी भागीदारी, खुलेंगे नए रास्ते

इन बदलावों से बाजार में तरलता, मूल्य खोज और वैश्विक बाजारों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित

नई दिल्ली ।

बाजार नियामक सेबी ने एक्सचेंज-ट्रैडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि इंडेक्स डेरिवेटिव्स और नकदी के बिना सेटल होने वाले गैर-कृषि ज़िंस डेरिवेटिव्स में एफपीआई को व्यापार की अनुमति देना है। सेबी का मानना है कि इन बदलावों से बाजार में तरलता, मूल्य खोज और वैश्विक बाजारों के साथ बेहतर

तालमेल स्थापित होगा। मंगलवार को जारी अपने परामर्श पत्र में सेबी ने दो प्रमुख प्रस्ताव रखे हैं। पहले प्रस्ताव के तहत, एफपीआई को अब गैर-कृषि इंडेक्स डेरिवेटिव अनुबंधों में भाग लेने की अनुमति मिलेगी, भले ही इनकी अंतर्निहित संपत्तियां नकदी में सेटल होती हों या नहीं। वर्तमान में, एफपीआई केवल नकदी में सेटल होने वाले गैर-कृषि डेरिवेटिव अनुबंधों में ही निवेश कर सकते हैं।

चूँकि इंडेक्स डेरिवेटिव्स का निपटान हमेशा नकदी में ही होता



0.54, निफ्टी पीएसई , निफ्टी इन्फ्रा और निफ्टी एनजी तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं व्यापक बाजार में मिलाजुला कारोबार हुआ। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की कमजोर शुरुआत हुई।

बैंकिंग में एआई का जिम्मेदारी से करें इस्तेमाल- आरबीआई गवर्नर

बैंक के फैसलों की जिम्मेदारी अंततः बैंक की ही होती है, न कि उसके एल्गोरिथ की



नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की नसीहत दी है।

एफआईबीसी 2026 सम्मेलन को संबोधित करते हुए मल्होत्रा ने साफ कहा कि एआई को नियंत्रित किए जाने वाले जोखिम के बजाय एक क्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए जिसका सावधानी से उपयोग हो। साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में आगाह किया कि बैंक के फैसलों की जिम्मेदारी अंततः बैंक की ही होती है, न कि उसके एल्गोरिथ की।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देशों के सदस्य तेज भुगतान प्रणाली को केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) से जोड़ने पर भी चर्चा कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने एआई मॉडल से जुड़े जोखिमों पर बोलते हुए

वस्तु निर्यात दूसरी तिमाही में 131 अरब डॉलर पार करेगा- एग्जिम बैंक

नई दिल्ली ।

भारत के निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) ने एक सकारात्मक अनुमान जारी करते हुए कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में देश का कुल वस्तु निर्यात 131.2 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

बैंक के बुधवार को जारी बयान के अनुसार यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। एग्जिम बैंक के विश्लेषण के मुताबिक इस वृद्धि में गैर-तेल निर्यात का बड़ा योगदान होगा, जिसके 20.3 प्रतिशत बढ़कर 113.8 अरब डॉलर होने की संभावना है।

इसी तरह, गैर-तेल और गैर-रतल एवं आभूषण निर्यात में भी 20.5 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान है, जिससे यह आंकड़ा 105.8 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्र निर्यात वृद्धि को गति प्रदान कर रहे हैं और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। इस अनुमान से देश की व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

बैंकिंग में एआई का जिम्मेदारी से करें इस्तेमाल- आरबीआई गवर्नर

कहा कि आरबीआई इसे क्षमता के रूप में देखता है। हालांकि, उन्होंने चेताया कि बैंकिंग प्रणाली में एआई अपनाने से मानवीय निर्णय क्षमता और जवाबदेही कम होने का जोखिम हो सकता है।

मल्होत्रा ने जोर दिया, हम यह नहीं कह सकते कि फैसला मॉडल ने किया। इसमें सार्थक मानवीय निगरानी, फैसले को समझाने और

हस्तक्षेप करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने इसे ब्लैक बॉक्स समस्या बताते हुए कहा कि एआई सिस्टम के किसी छोटे व्यवसाय को कर्ज न देने की सलाह देने पर, ऋणदाता और नियामक दोनों को कारण जानने का हक है। मल्होत्रा ने एआई में पक्षपात और भेदभाव

के जोखिम पर भी आगाह किया, खासकर अगर वह पुराने कर्ज के आंकड़ों पर आधारित हो।

उन्होंने थर्ड-पार्टी वेंडर पर निर्भरता और डेटा गोपनीयता के खतरों का भी जिक्र किया, कहा कि शाहकों को डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा कानून के पालन से कहीं ज़्यादा की उम्मीद करनी चाहिए।

आरबीआई गवर्नर ने भारतीय बैंकों को एआई अपनाने में पीछे न रहने पर जोर देते हुए कहा कि वैकल्पिक डेटा जैसे नकदी प्रवाह और जीएसटी फाइलिंग पर प्रशिक्षित एआई मॉडल ऋण आवंटन की लागत को कम कर सकते हैं।

टाटा संस के चेयरमैन पद से एन. चंद्रशेखरन ने दिया इस्तीफा



फरवरी 2027 तक पूरा करेंगे कार्यकाल

मुंबई ।

टाटा ग्रुप में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला है। एन. चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, हालांकि वह फरवरी 2027 तक अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे और दोबारा नियुक्ति नहीं मांगेंगे। इस निर्णय के पीछे टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की आपत्तियां और टाटा संस व टाटा ट्रस्ट्स के बीच गहरे मतभेद प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। नोएल टाटा ने फरवरी में उनकी दोबारा नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह फैसला टाल दिया गया था। दोनों संस्थाओं के बीच बोर्ड प्रतिनिधित्व, रणनीति और शापूज्जी पखेनजी समूह की हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर मतभेद थे। चंद्रशेखरन 1987 में टाटा ग्रुप से जुड़े थे और 2017 में टाटा संस के चेयरमैन बने थे। यह इस्तीफा 18 अगस्त की एजीएम से ठीक पहले आया है, जहां उनकी दोबारा नियुक्ति पर शेयरधारकों की वोटिंग होनी थी। यह कदम टाटा ग्रुप के शीर्ष नेतृत्व में एक अहम बदलाव है।

ग्रामीण भारत और छोटे व्यवसायों को एआई से सशक्त करें- एसबीआई चेयरमैन

तकनीक की वास्तविक परीक्षा बारीकियों में नहीं, उपलब्धियों में



नई दिल्ली ।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सीएसए शोही ने बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को ग्रामीण शाहकों, छोटे व्यवसायों और कृषि करने के अपनाना जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह भारत के 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। शोही ने स्पष्ट किया कि एआई की वास्तविक परीक्षा उसकी बारीकियों में नहीं, बल्कि उससे हासिल होने वाली उपलब्धियों में है। उन्होंने जोर दिया कि एआई को अर्थव्यवस्था में गहराई तक ले जाना होगा, खासकर ग्रामीण भारत, छोटे कारोबारियों और पारंपरिक ऋण मॉडल में शामिल न होने वाले शाहकों तक। उन्होंने बताया कि

एआई कृषि क्षेत्र में जोखिम आकलन, डिजिटल रिकॉर्ड और सैटेलाइट इमेज के माध्यम से ऋण पहुंच और पोर्टफोलियो प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, शोही ने स्वीकार किया कि कुछ एआई तकनीकों को कृषि ऋण में पहले से अपनाना जा रहा है, लेकिन चुनौती उन्हें पायलट प्रोजेक्ट से आगे ले जाकर अंतिम छोर तक किफायती और व्यावहारिक बनाने की है। उन्होंने आगाह किया कि एआई के बढ़ते उपयोग से साइबर सुरक्षा जैसे नए जोखिम उत्पन्न होंगे, क्योंकि यह हमलावरों को अधिक परिष्कृत खतरों विकसित करने की अनुमति दे सकता है। बैंकों को अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी और विश्वास बनाए रखने के लिए अपने ढांचे पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि एआई सिस्टम अधिक स्वायत्त हो जाएंगे।

